mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-232 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
22 अगस्त 2026 शनिवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

: ब्रीफ बॉक्स :

एनटीए बोला- 'आंसर की' पर फीस लेना पैसा कमाना नहीं

स्टूडेंट की आपत्ति सही तो पैसे वापस बाकी छात्रों को भी फायदा मिलेगा

नई दिल्ली,एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने एग्जॉम के बाद जारी 'आंसर की' को चैलेंज करने वाली फीस पर गुरुवार को सफाई दी। NTA ने कहा- आंसर की में अगर किसी सवाल का जवाब गलत लगता है तो उम्मीदवार चैलेंज कर सकता है। इसके लिए हर सवाल पर 200 फीस देनी होती है।

एजेंसी ने कहा कि फीस इसलिए है, ताकि बेवजह की आपत्तियां न आएं। इसका मकसद छात्रों से पैसे कमाना नहीं है। यानी अगर आपको सच में आंसर की में गलती मिली है और आपकी आपत्ति सही है तो पैसे भी वापस मिलेंगे और लाखों छात्रों का रिजल्ट सही हो सकता है।

तेलंगाना सीएम रेड्डी को अमेरिका जाने की परमिशन नहीं मिली

हैदराबाद,एजेंसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

CMO के मुताबिक, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाला तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरा नहीं कर सकेगा। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लियरेंस देने से इनकार किया है।

रेवंत रेड्डी फिलहाल लंदन में हैं। उन्हें अमेरिका के बोस्टन जाना था और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटना था, लेकिन अब वे 23 अगस्त को सीधे हैदराबाद लौटेंगे।

हालांकि, सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को अमेरिका जाए बिना वहां के संस्थानों के साथ सभी रूब और साझेदारी समझौते पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

पहले से तय थाच और स का दौरा: रेवंत रेड्डी 20 अगस्त को लंदन पहुंचे थे। च दौरे में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन बिजनेस स्कूल के कार्यक्रम शामिल थे। उन्हें एमिरेट्स स्टेडियम में EPL फुटबॉल से जुड़े कार्यक्रम में भी जाना था।

पीएम मोदी का शीर्ष नौकरशाहों को निर्देश, युवाओं और विश्वविद्यालयों से बढ़ाएं जुड़ाव

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि नीति निर्माण में नए दृष्टिकोण के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच जुड़ाव बढ़ाया जाना चाहिए। लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने मानवीय हस्तक्षेप और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बनाए रखते हुए एआइ के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया।

पीएम ने सचिवों से कहा कि उन्हें देश के भविष्य को आकार देने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मोदी ने नीति निर्माण में नए दृष्टिकोण लाने के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की आवश्यकता पर बल दिया।

सिखों की रिहाई के लिए पंजाब बंद

लुधियाना समेत 4 जिलों में दुकानें बंद करवाई

» हाईवे जाम करने पर बहस, आप विधायक की बस रोकी

चंडीगढ़/मोहाली,एजेंसी। कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से आज (21 अगस्त) सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद रहा। बसों के साथ सभी प्राइवेट स्कूल बंद है। हालांकि ट्रेनों पर अभी तक कोई असर देखने को नहीं मिला है।

खरड़-चंडीगढ़ हाईवे को बंद कर दिया गया है। यहां ड्यूटी पर जाने वाले लोगों की मोर्चा के सदस्यों से बहस हो गई। मोहाली में निहंगों ने पिज्जा शॉप बंद कराई। उधर, अमृतसर, पटियाला और लुधियाना में कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने खुली दुकानों को बंद करवाया। इससे पटियाला में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, फरीदकोट में प्रदर्शनकारियों ने आप विधायक डिंपी ढिल्लों की बस को रोक दिया। बस को रोके जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बस को वापस बस स्टैंड भेज दिया।

जालंधर, पठानकोट और लुधियाना में बंद का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। यहां कुछ जगह बाजार पूरी तरह बंद हैं तो कई जगह दुकानें खुली हैं। हालांकि मोर्चा के सदस्यों ने दुकानों को बंद करने की अपील की।

इस बीच चंडीगढ़ BJP के स्टेट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ई-मेल में पंजाब बंद रखने और बंद के दौरान खुले रहने वाले शहरों में बम धमाके करने का भी जिक्र है। इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और जांच शुरू की। मोर्चा सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद सिखों की रिहाई और पूर्व प्रधानमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार हवारा की पैरोल की मांग कर रहा है।

पाकिस्तान नहीं चीन हमारी सबसे बड़ी चुनौती, सेना को तैयार रहना होगा : पूर्व सेना प्रमुख नरवणे

मुंबई,एजेंसी। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा और दूरदर्शी बयान दिया है। अपनी नई पुस्तक के विमोचन पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में पाकिस्तान से मिलने वाली आतंकवाद की चुनौती के कारण भारत का ध्यान उस पर अधिक केंद्रित रहा है, लेकिन लंबी अवधि में चीन ही भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी होगा।

जनरल नरवणे ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए चीन के लिए दुश्मन शब्द का प्रयोग करने से परहेज किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को बातचीत का रास्ता खुला रखने के साथ-साथ अपनी सैन्य प्रतिरोध क्षमता को भी बेहद मजबूत बनाए रखना होगा।

पाकिस्तान और चीन के बीच का अंतर: सुरक्षा चुनौतियों पर बात करते हुए पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ भारत के अनसुलझे सीमा विवाद हैं और युद्ध का इतिहास रहा है, लेकिन दोनों देश पूरी तरह से अलग श्रेणी में आते हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे निरंतर समर्थन के कारण भारत का तात्कालिक ध्यान अपनी पश्चिमी सीमा पर केंद्रित रहता है।

वार्ता पहली प्राथमिकता, सैन्य तैयारी अनिवार्य... नरवणे ने जोर देकर कहा कि भारत को बल प्रयोग के बजाय कूटनीतिक तंत्र और बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति का उपयोग हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए।

हालांकि, लंबे समय में चीन राजनीति, अर्थशास्त्र, व्यापार और सैन्य मामलों सहित सभी क्षेत्रों में भारत का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि जहां प्रतिस्पर्धा होती है, वहां संघर्ष की गुंजाइश भी बनी रहती है।

हालांकि, किसी भी संभावित दुस्साहस को रोकने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का हर समय तैयार रहना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई देश शांति चाहता है, तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा ताकि एक मजबूत सैन्य निरोध स्थापित किया जा सके। क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करते हुए उन्होंने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में शांति बनाए रखने पर बल दिया।

21 भारतीयों वाले जहाज पर ईरानी हमले का वीडियो सामने

● होर्मुज में आईआरजीसी बोट्स ने फायरिंग की ● शीशे टूटे, सामान बिखरा, क्रू ने छिपकर जान बचाई

नई दिल्ली,एजेंसी। होर्मुज स्ट्रेट में 21 भारतीय नाविकों वाले एक कंटेनर जहाज पर ईरानी नौकाओं ने फायरिंग की थी। यह घटना 22 अप्रैल को हुई थी। भारतीय नाविकों के संगठन (FSUI) ने अब इस घटना का वीडियो जारी किया है।

वीडियो में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) से जुड़ी नौकाओं को जहाज के आसपास देखा जा सकता है। जहाज पर फायरिंग के बाद शीशे टूटे और सामान बिखरा दिखाई देता है। एक जगह रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे जाने का सीन भी दिखता है।

हमले के दौरान जहाज का क्रू अपनी जान बचाने के लिए अंदर छिप गया। जहाज पर 21 भारतीय नाविक सवार थे और सभी सुरक्षित रहे।

यह फैसला ऐसे समय लिया गया था, जब होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के इलाकों में हुए हमलों में भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र में हुए हमलों में कम से कम 14 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है।

भारत ने जहाज मालिकों, जहाज मैनेजमेंट कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली RPSL कंपनियों को अरब की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे।

यह रोक भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर है। भारत के बाहर से विदेशी शिपिंग कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए नाविकों पर यह आदेश सीधे लागू नहीं होगा।

होर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगा चुकी सरकार... खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच भारत ने 16 जुलाई को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी थी। यह रोक अगले आदेश तक लागू है।

डीआर कांगो में इबोला के बुंडिबुग्यो वायरस के खिलाफ 70 हजार वैक्सीन की मंजूरी

डीआर कांगो,एजेंसी। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआर कांगो) में इबोला के बुंडिबुग्यो वायरस बीमारी का प्रकोप जारी है। इस बीच देश की सरकार ने इबोला वैक्सीन की वैश्विक व्यवस्था से वैक्सीन की मांग की थी। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ऑन वैक्सीन प्रोविजन (आईसीजी) ने डीआर कांगो को तुरंत 70 हजार खुराक देने की मंजूरी दी है। इस फैसले को बीमारी से प्रभावित लोगों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन 70 हजार खुराक में से 50 हजार खुराक का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रंटलाइन और स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाने के लिए किया जाएगा। बाकी 20 हजार खुराक का इस्तेमाल एक बड़े वैज्ञानिक अध्ययन यानी तृतीय चरण क्लिनिकल ट्रायल में किया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इरवेबो वैक्सीन बुंडिबुग्यो वायरस से लोगों को कितनी सुरक्षा दे सकती है।

इरवेबो वैक्सीन पर बड़ा सवाल: इरवेबो एक ऐसी वैक्सीन है जिसे इबोला वायरस बीमारी के एक खास प्रकार, जिसे पहले जायर इबोलावायरस कहा जाता था, के खिलाफ इस्तेमाल के लिए लाइसेंस और सिफारिश मिली हुई है। लेकिन बुंडिबुग्यो वायरस इससे अलग है। इसलिए अभी यह साफ नहीं है कि इरवेबो वैक्सीन बुंडिबुग्यो वायरस से संक्रमित होने से इंसानों को बचा सकती है या नहीं।

वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला और जानवरों पर किए गए शुरुआती अध्ययनों से कुछ उम्मीद जरूर मिली है। इन अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि यह वैक्सीन कुछ हद तक सुरक्षा दे सकती है। हालांकि, इंसानों में इसके प्रभाव को लेकर अभी पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं। यही वजह है कि क्लिनिकल ट्रायल को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आठ राज्यों में डीएम को मिला भारतीय नागरिकता देने का अधिकार

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, असम व त्रिपुरा (आदिवासी इलाकों को छोड़कर) और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में जिलाधिकारियों (डीएम) को भारत के बाहर जन्मे उन पात्र एवं उपयुक्त आवेदकों को नागरिकता देने का अधिकार दिया, जो आम तौर पर इन क्षेत्रों में रह रहे हैं। सरकार ने बुधवार को नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की, जिसमें उक्त इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जिलाधिकारियों को पंजीकरण या नेचुरलाइजेशन के जरिये नागरिकता चाहने वाले आवेदनों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

अधिसूचित नियमों में कहा गया है, 'जिलाधिकारी, आवेदक की उपयुक्तता से संतुष्ट होने यानी यह तय करने पर कि वह पंजीकरण या नेचुरलाइजेशन के लिए एक पात्र व उपयुक्त व्यक्ति है, उसे भारत की नागरिकता प्रदान करेगा।'

इन राज्यों में जिलाधिकारी उन अधिकार प्राप्त समितियों और जिला स्तरीय समितियों की जगह लेंगे, जिनके पास पहले ये अधिकार थे। सरकार ने निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त समितियों या जिला स्तरीय समितियों के पास वर्तमान में लंबित सभी आवेदनों को तुरंत संबंधित जिलाधिकारियों को स्थानांतरित किया जाए। नए नियमों में आवेदकों के लिए खुद पेश होने की सख्त शर्तें रखी गई हैं। नियमों में कहा गया है, 'अगर कोई आवेदक उचित मौके दिए जाने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए खुद पेश नहीं होता है, तो कलेक्टर आवेदन को खारिज कर देगा।

सीएम योगी को 'फ्री हैंड': टिकट बंटवारे से लेकर रणनीति बनाने का काम खुद तय करेंगे

» 2027 के लिए भाजपा का बड़ा दांव

लखनऊ,एजेंसी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'फ्री हैंड' दे दिया है। अब चुनाव में उम्मीदवार चुनने से लेकर पूरी रणनीति बनाने तक की कमान सीधे सीएम योगी के हाथों में होगी।

दिल्ली से लेकर लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की चर्चा जोरों पर है। सीएम योगी ने इस दिशा में अपने चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया है।

नतीजा यह रहा कि 47 में से 26 सांसद चुनाव हार गए। बीजेपी नीत गठबंधन यूपी में महज 36 सीटों पर सिमट गया, जिसकी वजह से केंद्र में पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऋस और पार्टी के एक बड़े धड़े ने इस पर गंभीर सवाल उठाए थे।

लोकसभा चुनाव के नतीजों से केंद्रीय नेतृत्व ने लिया सबक... 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को एक लिस्ट सौंपी थी। इसमें करीब दो दर्जन से ज्यादा सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देने की सलाह दी गई थी। लेकिन आलाकमान ने इस सिफारिश को दरकिनार कर 64 में से 47 सांसदों को दोबारा मैदान में उतार दिया।

मोबाइल के लिए पैसे नहीं मिले तो मां का मर्डर, चप्पल से खुला राज

मोतिहारी,एजेंसी। 'मेरे पास पैसे नहीं थे। मां से मांगा तो उसने डांट कर भगा दिया। मुझे नशा के लिए पैसे चाहिए थे। गुस्से में आकर मैंने बाजार से 350 रुपए में एक धारदार चाकू खरीदा। मां को बहाने से खेत में ले गया और वहां पीछे से करीब 4 बार पीठ पर चाकू मारा। इस बीच मां ने मुझसे कहा- बेटा हमको छोड़ दो, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।' ये कहना है मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के रहने वाले आलम हुसैन (24) का, जिसने मोबाइल के लिए 35 हजार रुपए अपनी मां से मांगे थे, पैसे नहीं मिले तो हत्या कर दी। मर्डर करने के 10 मिनट बाद आरोपी आलम को अफसोस हुआ और वो घर पहुंचकर जोर-जोर से रोने लगा।

ट्रम्प बोले- होर्मुज पर जल्द अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा

ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म, उसके पास सिर्फ कुछ मिसाइल और ड्रोन बचे

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिका जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री लीडरशिप को बहुत नुकसान हुआ है।

ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करना जरूरी था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ईरान की ओर से फिर ऐसा खतरा पैदा हुआ, तो अमेरिका फिर से कड़े कदम उठाएगा।

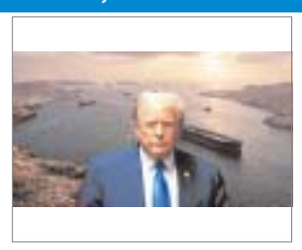

बातचीत मुश्किल: ट्रम्प ने कहा कि ईरान के कई बड़े नेता अब नहीं रहे। इसके चलते नए समझौते पर बातचीत मुश्किल हो गई है। फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है। ट्रम्प ने एक बार फिर से दावा किया कि ईरान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई बहुत ज्यादा है। सेना को वेतन देने में भी दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल, अमेरिका ने गुरुवार को ईरान पर नई आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। इसका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाकर उसे परमाणु कार्यक्रम खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए मजबूर करना है।

अमेरिका पहले ही ईरान के तेल, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। अब वह ईरान से जुड़े दूसरे देशों और कंपनियों पर भी दबाव बढ़ाने की तैयारी में है।

अमेरिका ने ईरान की मदद करने वालों को चेतावनी दी... अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों को चेतावनी दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बैसेट ने कहा कि जो लोग ईरान के साथ कारोबार जारी रखेंगे, उनके खिलाफ अमेरिका कड़े आर्थिक कदम उठा सकता है।

एमपी-यूपी की 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर

● हिमाचल में अब तक 219 मौतें ● राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 40ए पार

नई दिल्ली,एजेंसी। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नर्मदा, मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा, घाघरा, शारदा, टोंस, सोन और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के दौरान बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़ और अन्य घटनाओं में 219 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 131 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई।

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण गुरुवार को श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया।

इन राज्यों में सामान्य से अधिक तापमान: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा। वहीं ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी तापमान अधिक दर्ज किया गया।

रात में भी गर्मी से राहत नहीं: वहीं, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम-त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री से अधिक रहा। इससे रात के समय भी लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा।

कई इलाकों में अच्छी बारिश... मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सुबह 8:30 बजे से अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में त्रिपुरा के कैलाशहर एपी में 90 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुड्डालोर में 60 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

कालकाजी में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के बीच बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर होगी सख्त कार्रवाई

नईदिल्ली, एजेंसी। कालकाजी फ्लाईओवर की दूसरी लेन और मोदी मिल फ्लाईओवर तक इसके एक्सटेंशन का काम एक पखवाड़ा पहले शुरू हुआ। बैरिकेडिंग के चलते सड़क संकरी हो चुकी है। ट्रैफिक दबाव के साथ ही गलत दिशा में आ रहे वाहनों के कारण सुबह-शाम जाम की स्थिति बन रही है। ओखला फेज-तीन समेत एयरपोर्ट जाने वालों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम पूरा होने तक बनी रहेगी, जो लगभग तीन वर्षों तक चलेगा। हालांकि गलत दिशा में चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात करने और व्यावसायिक वाहनों को डायवर्ट कर जाम से कुछ राहत दिलाने पर ट्रैफिक पुलिस विचार कर रही है। एक-दो दिनों में जाम वाले प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे। आउटर रिंग रोड पर लगभग 100 मीटर तक

डिवाइडर के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर पिलर के लिए खोदाई का काम चल रहा है। निर्माण कार्य के कारण एक तो सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, वहीं दोनों तरफ वाहन चार्जिंग व बैटरी स्वाइपिंग प्वाइंट भी हैं। मोदी मिल फ्लाईओवर से उतरते ही वाहन चालक ओखला फेज-3 जाने के लिए गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। वहीं फ्लाईओवर के नीचे बने यूटर्न में भी ओखला मंडी जाने के लिए वाहन चालक गलत दिशा में चले जाते हैं। इससे भीषण जाम की स्थिति बन रही है। जाम वाले ऐसे तीन-चार प्वाइंट हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती हो जाने से काफी राहत होगी।

ट्रैफिक की रफ्तार कम होगी पर रहेगी सुचारू

दक्षिणी दिल्ली रेंज के पुलिस उपायुक्त यातायात संदीप गुप्ता के मुताबिक एमबी रोड के साथ ही खानपुर से मूलचंद मार्ग पर भी मेट्रो का काम चल रहा है। सड़कें वहां भी संकरी हैं। ऐसे में उन मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों को डायवर्ट करना समस्या को और बढ़ा देगा। हालांकि गलत दिशा वाले वाहनों पर सख्ती और जाम वाले प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करने से यातायात काफी हद तक सुचारू रहेगा। लोगों की राहत के लिए जल्द ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे।

सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की साइट पर पहुंचने लगी निर्माण सामग्री

आउटर रिंग रोड पर कालकाजी फ्लाईओवर के बाद अब सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की दूसरी लेन का भी काम जल्द शुरू होगा। लगभग 412 करोड़ रुपये की दोनों परियोजना दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को कम करने में कारगर साबित हो सकती है। सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के नजदीक ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन की खाली जमीन को घेरा जा रहा है, जहां निर्माण सामग्री भी आनी शुरू हो चुकी है।

पीएम मोदी के डिग्री पर सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट में अब 29 सितंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक की डिग्री की जानकारी देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 29 सितंबर को सुनवाई करेगा। बृहस्पतिवार को मामले पर सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने मामले को अन्य तारीख पर सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 29 सितंबर के लिए तय कर दिया।

एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती: अपीलकर्ता ने प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को रद करने के एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी है। अपीलकर्ता के वकील ने गुरुवार को कहा कि पिछली बार कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपील दायर करने में हुई देरी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया था।

कंझावला-बवाना-घेवरा-मदनपुर लिंक रोड का निर्माण छह माह बाद भी अधूरा, वाहन मालिकों की बढ़ी मुश्किलें

नईदिल्ली, एजेंसी। कंझावला-बवाना-घेवरा-मदनपुर लिंक रोड का निर्माण फरवरी 2026 में शुरू होने के करीब छह माह बाद भी पूरा नहीं हो सका। निर्माण कार्य की धीमी गति और सड़क पर जगह-जगह पड़े मलबे के कारण इस मार्ग से रोजाना आवागमन करने वाले हजारों ग्रामीणों, वाहन चालकों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने से स्थिति और खराब हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह लिंक रोड कंझावला, बवाना, घेवरा और मदनपुर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। करीब 100 फुट चौड़ी इस सड़क के लिए वर्ष 1998 में कंझावला गांव की चकबंदी के दौरान जमीन छोड़ी गई थी। इसके बाद से ग्रामीण इस मार्ग के निर्माण और विकास की मांग करते आ रहे हैं।

क्षेत्र में सैकड़ों छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां: फरवरी 2026 में निर्माण शुरू होने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि जल्द ही उन्हें बेहतर और सीधा संपर्क मार्ग मिलेगा, लेकिन छह माह बाद भी काम अधूरा होने से लोगों की परेशानी बरकरार है। इस मार्ग का इस्तेमाल आसपास के गांवों के लोग खेतों और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए करते हैं। क्षेत्र में सैकड़ों छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं। सड़क पर निर्माण सामग्री और मलबा पड़े होने से कार, मोटरसाइकिल, टेंपो समेत अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर लोगों को मलबे और पानी के बीच से रास्ता बनाकर निकलना पड़ रहा है। लिंक रोड बनने से घेवरा की ओर से बवाना जाने वाले लोगों को काफी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं कंझावला और बवाना से मदनपुर व आसपास के गांवों में जाने वाले लोगों को भी सीधा रास्ता मिलेगा।

वर्तमान में लोगों को वैकल्पिक मार्गों से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत होती है। स्थानीय लोगों ने सड़क का निर्माण जल्द पूरा कराने के साथ फिलहाल मलबा हटाकर रास्ता समतल कराने की मांग की है। जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक कम से कम सड़क पर पड़े मलबे को मशीन से समतल कर दिया जाए, ताकि दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही सुचारु हो सके। - सियाराम मौर्य, स्थानीय निवासी सड़क का निर्माण जल्द पूरा होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में मलबे और खराब रास्ते के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क जल्द तैयार होने से ग्रामीणों के साथ औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। - वेदप्रकाश, स्थानीय निवासी संबंधित सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी ने बताया कि सड़क का निर्माण करीब छह माह में पूरा किया जाना था, लेकिन बारिश और त्योहारों के कारण काम प्रभावित हुआ। अब विभाग की कोशिश है कि इसी वर्ष सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाए। फिलहाल लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए सड़क पर पड़े मलबे को मशीन से समतल कराया जाएगा, ताकि वाहनों की आवाजाही में परेशानी न हो।

अमेरिका ने हिजबुल्ला के कैश नेटवर्क पर लगाया प्रतिबंध

10 लोगों पर कार्रवाई; क्या लगाए आरोप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके कथित कैश नेटवर्क से जुड़े 10 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला को दोबारा ईरान के प्रॉक्सी संगठन के रूप में चिन्हित किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्ला की सैन्य गतिविधियां और उसकी फंडिंग व्यवस्था सीधे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स **(आईआरजीसी-क्यूएफ) से जुड़ी हैं:** अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए 10 लोग ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो हिजबुल्ला तक बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने का काम करता था। इस नेटवर्क के जरिए कथित तौर पर करोड़ों डॉलर की रकम अलग-अलग देशों के बीच पहुंचाई जाती थी।

हवाई यात्राओं के जरिए पहुंचाई जाती थी नकदी: अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक, इस नेटवर्क में शामिल कैश कूरियर कमर्शियल एयरलाइनों से यात्रा करते थे। वे लेबनान, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

और ईरान के बीच आवाजाही करते हुए बड़ी रकम एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते थे। अमेरिका का आरोप है कि इस तरीके से हिजबुल्ला को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने में मदद मिलती थी। इससे संगठन अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में भी सक्षम होता था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए सैकड़ों मिलियन डॉलर तक की रकम अलग-अलग देशों के बीच स्थानांतरित की गई।

ईरान के लिए काम करने का आरोप: अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, हिजबुल्ला को ईरान के आईआरजीसी-क्यूएफ के विस्तार के रूप में देखे जाने की स्थिति को दोबारा स्पष्ट किया गया है। अधिकारी ने कहा कि संगठन की सैन्य गतिविधियां, बाहरी सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां और बड़े वित्तीय नेटवर्क आईआरजीसी-क्यूएफ के साथ मिलकर काम करते हैं। अमेरिका का कहना है कि हिजबुल्ला को केवल एक स्वतंत्र लेबनानी संगठन के रूप में नहीं देखा जा सकता। उसके अनुसार, संगठन ईरान की क्षेत्रीय और विदेशों में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पहले से आतंकवादी संगठन घोषित: अमेरिका पहले से ही हिजबुल्ला और आईआरजीसी-क्यूएफ, दोनों को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में रखता है। नई कार्रवाई के तहत हिजबुल्ला के वित्तीय नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई है। हिजबुल्ला लेबनान में एक राजनीतिक दल के साथ-साथ एक सशस्त्र संगठन भी है। उस पर लंबे समय से इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ सशस्त्र गतिविधियां चलाने के आरोप लगते रहे हैं।

इस्राइल-लेबनान शांति प्रयासों के बीच कार्रवाई: अमेरिका की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब ट्रंप प्रशासन इस्राइल और लेबनान के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका हिजबुल्ला की वित्तीय क्षमता को कमजोर करने और ईरान से उसके संबंधों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है।

हैदराबाद में रफ्तार का कहर, एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से महिला की मौत; सांसद के बेटे पर केस दर्ज

हैदराबाद, एजेंसी। हैदराबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से एक 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। आरोप है कि कार राज्यसभा सांसद लिंगामनेनी रमेश के बेटे लिंगामनेनी संजुश (21) चला रहे थे। पुलिस ने उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। घटना 16 अगस्त को माधापुर इलाके में इनऑर्बिट मॉल के पास हुई। पीड़ित भारती मुखी लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्सवुमन के रूप में काम करती थीं। दोपहर करीब 3 बजे वह और उनकी सहकर्मी पूजा अशोक अलोने लंच के लिए आईटीसी कोहेनुर इलाके गई थीं। वापस लौटते समय जब भारती सड़क पार कर रही थीं, तब एस्टन मार्टिन कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक, कार तेज गति और लापरवाही से चलाई जा रही थी। भारती को सिर में गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। उन्हें उसी कार में जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी सहकर्मी ने स्टोर मैनेजर को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को फोन किया। साइबराबाद पुलिस ने लिंगामनेनी संजुश की पहचान ड्राइवर के रूप में की है। उनके पिता आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से राज्यसभा सांसद और व्यवसायी हैं। माधापुर एसीपी सी. श्रीधर ने बताया कि आरोपी को नोटिस भेजा गया है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्योंकि अपराध जमानती है और अधिकतम सजा सात साल से कम है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) के तहत दर्ज किया गया है, जो लापरवाही से मृत्यु कारित करने से संबंधित है।

उत्तराखंड में 18 प्रोजेक्ट में 84 प्रतिशत काम पूरा, दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को मिलेगी पक्की छत

देहरादून, एजेंसी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत उत्तराखंड में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अपने पक्के घर का सपना जल्द साकार होने जा रहा है।प्रदेश में योजना के तहत 18 परियोजनाओं में 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 12,948 यानी करीब 84 प्रतिशत मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने का है। आवास विभाग ने लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की है। कार्यदायी संस्थाओं को सभी लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 1,271 मकानों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं।

हरिद्वार के 503 लाभार्थी शामिल

इनमें रुड़की के 768 और हरिद्वार के 503 लाभार्थी शामिल हैं। योजना के तहत सबसे अधिक 10,200 आवास ऊधमसिंह नगर जिले में बनाए जा रहे हैं। रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1,872 आवास तैयार हो चुके हैं। भवानीपुर (जसपुर) में 1,264, उकरौली-1 (सितारगंज) में 1,168, उकरौली-2 में 864, कनकपुर (काशीपुर) में 1,256, मटकोटा (रुद्रपुर) में 928, श्यामनगर (गदरपुर) में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर (काशीपुर) में 512 और गंगापुर गोसाल में 584 आवास बनाए जा रहे हैं। झब्बरपुर में 448, अन्नेखी में 1,152, बेल्दी में 1,088, शिकारपुर में 768 और इंद्रलोक आवासीय योजना में 528 आवास शामिल हैं। नैनीताल के उम्मेदनगर (रामनगर) में सभी 528 आवास बन चुके हैं। देहरादून की धौलास हाउसिंग स्कीम में 240 में से 180 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य

सचिव आवास आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराना है। योजना में राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जा रही है। सरकार के अनुसार इससे पात्र परिवारों को आवास निर्माण में अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके सम्मान, सुरक्षा तथा बेहतर भविष्य की मजबूत नींव तैयार होगी।

ईरान के ड्रोन हमलों के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, जानें क्यों बंद की यूरोप की अहम यूनिट

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना ने यूरोप में ड्रोन युद्ध की तकनीक पर काम कर रही अपनी एक विशेष यूनिट को बंद करने का फैसला किया है। यह यूनिट पिछले करीब एक साल से ड्रोन बनाने, उनका इस्तेमाल करने और युद्ध के दौरान ड्रोन से लड़ने की रणनीति पर प्रयोग कर रही थी। अब इसे दोबारा एक पारंपरिक एयरबोर्न इन्फैंट्री बटालियन के रूप में काम करने का निर्देश दिया गया है। यह यूनिट इटली और जर्मनी में तैनात 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड का हिस्सा है। पिछले साल नवंबर में करीब 600 सैनिकों की एक बटालियन को विशेष रूप से ड्रोन युद्ध के लिए तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीक और रणनीति विकसित करना था, जिसे जरूरत पड़ने पर किसी भी युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके। यूक्रेन युद्ध से मिली सीख पर बना था फोकस अमेरिकी सेना ने यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध में ड्रोन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से सीख लेने के लिए यह प्रयोग शुरू किया था। यूक्रेन ने युद्ध में कम लागत वाले ड्रोन, खासकर ड्रोन, का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड के सैनिक इटली में एक विशेष ड्रोन लैब में अपने हमलावर ड्रोन भी तैयार कर रहे थे। सेना के मुताबिक, सैनिक ड्रोन के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे ड्रोन विकसित करने पर भी काम कर रहे थे, जिन्हें दुश्मन की जैमिंग तकनीक से बचाया जा सके।

जांच के बाद जेल भेजे गए इमरान खान: छह डॉक्टरों की टीम ने किया चेकअप

● नौ महीने बाद पत्नी और बहन से हुई मुलाकात

इस्लामाबाद, एजेंसी। पीटीआई संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मेडिकल जांच के बाद वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें हिरासत में रखना सुरक्षित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल में जांच और इलाज का आदेश दिया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे रजिस्ट्रार कार्यालय ने आपत्तियों के साथ वापस कर दिया। इस बीच इमरान खान को बनी गाला भेजने और विदेश में इलाज कराने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पीटीआई का कहना है कि जेल की परिस्थितियां उनकी सेहत पर असर डाल रही हैं, जबकि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उम्मीद की नई किरण बताया है।

छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने की जांच: जानकारी के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री की छह विशेषज्ञ डॉक्टरों वाली टीम ने मेडिकल जांच की। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि इमरान खान को अस्पताल में भर्ती रखने की तत्काल जरूरत नहीं है और उन्हें जेल

में सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद जेल अधिकारियों ने उन्हें वापस अदियाला जेल पहुंचाया, जहां उन्हें उनकी सेल में भेज दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात: इमरान खान के अस्पताल पहुंचने से पहले इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरों ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

अस्पताल के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, इमरान खान की मेडिकल जांच और जरूरत पड़ने पर उन्हें भर्ती करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। जिसके बाद खान को इलाज के लिए भेजा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन में अस्पताल भेजने का दिया था आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करने के बाद उन्हें दो दिनों के भीतर किसी चिकित्सा संस्थान में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की। हालांकि, गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने कुछ आपत्तियां उठाते हुए सरकार की पुनर्विचार याचिका वापस कर दी।

2022 में सत्ता से हटने के बाद बढ़ीं कानूनी मुश्किलें

इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं। वह अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इमरान खान और उनकी पार्टी इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही है। पीटीआई का आरोप है कि इमरान खान को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर, सरकार और अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताते रहे हैं।

नौ महीने बाद पत्नी और बहन से मिले इमरान

इमरान खान ने मंगलवार को अदियाला जेल में अपनी पत्नी बुशरा बीबी और बहन नोरीन नियाजी से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल यह पहली बार था जब उनकी परिवार के इन सदस्यों से मुलाकात हुई। इससे पहले करीब नौ महीने तक दोनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जेल सूत्रों के हवाले से बताया कि क्रिकेट प्रमुख ने अपनी बहन के साथ करीब 15 मिनट बातचीत की। वहीं, बुशरा बीबी के साथ उनकी मुलाकात लगभग 30 से 35 मिनट चली।

अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की सजा: 2025 में इमरान खान को जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि अल-कादिर ट्रस्ट के जरिए इमरान खान और उनकी पत्नी को रिश्वत के तौर पर जमीन मिली थी। इसके अलावा 2024 में उन्हें एक गोपनीय राजनयिक केबल सार्वजनिक करने के मामले में भी दोषी ठहराया गया था। यह केबल 2022 में वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत ने इस्लामाबाद भेजी थी। हालांकि, तमाम कानूनी मामलों और जेल में लंबे समय से बंद रहने के बावजूद इमरान खान की राजनीतिक पकड़ खत्म नहीं हुई है। क्रिकेट के समर्थकों के साथ-साथ देश के युवा मतदाताओं के बीच भी उन्हें अब तक व्यापक समर्थन हासिल है।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान

छह स्व-सहायता समूहों को 13.50 लाख रुपये का ऋण वितरित, अधिकारियों ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश के साथ सीधी जिले में भी 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान संचालित किया जा रहा है अभियान का उद्देश्य सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है इसी क्रम में पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टमसार में जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम एवं शिविर आयोजित किया गया कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय, वनमण्डलाधिकारी प्रीति अहिरवार, उप संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी राजेश कन्ना टी. सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं था उनके शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण प्राथमिकता: मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण न किया जाए, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी समस्याओं और शासकीय सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें प्रशासन को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करते हुए आमजन तक पहुंचना होगा। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शासन और नागरिकों के बीच संवाद एवं विश्वास को मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल है।

योजनाओं की जानकारी के लिए लगाए स्टॉल: शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और पात्रता संबंधी जानकारी देने के लिए विभागवार स्टॉल लगाए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को संबंधित योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ नियमानुसार उसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया की जानकारी भी दी।

छह समूहों को मिला 13.50 लाख रुपये का ऋण: मुख्यमंत्री जन-विश्वास कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कुसमी द्वारा छह स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों के विस्तार के लिए कुल 13.50 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। आंचल स्व-सहायता समूह ठढ़ीपाथर को 1.50 लाख, पलक स्व-सहायता समूह टमसार को 3 लाख, गुलाब स्व-सहायता समूह टमसार को 3 लाख, सीता स्व-सहायता समूह टमसार को 3 लाख, अष्टभुजी स्व-सहायता समूह टमसार को 1.50 लाख तथा शारदा स्व-सहायता समूह टमसार को 1.50 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया इससे समूहों को अपनी आजीविका गतिविधियों का विस्तार करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी।

बस से पहुंचे जिला स्तरीय अधिकारी: शासकीय कार्यों में मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय अधिकारी सामूहिक रूप से बस से टमसार पहुंचे अधिकारियों का एक साथ बस से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना शासकीय संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और सामूहिक कार्यसंस्कृति का उदाहरण रहा। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने खण्ड स्तरीय कार्यालयों का निरीक्षण कर विभागीय कार्यों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बाढ़ नियंत्रण पर कागजी नहीं, जमीनी जरूरतों के हिसाब से बने प्लान

किसान नेता रामजीत सिंह बोले- नदी-नालों को अतिक्रमण मुक्त कर गहरीकरण और चौड़ीकरण जरूरी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्य प्रदेश किसान सभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं किसान नेता रामजीत सिंह ने जिले में बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए केवल कागजी योजनाएं बनाने के बजाय वैज्ञानिक आधार पर जमीनी जरूरतों के अनुरूप ठोस कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है उनका कहना है कि पानी की आवक और निकासी के बीच संतुलन बनाए बिना बाढ़ नियंत्रण की कोई भी योजना प्रभावी नहीं हो सकती रामजीत सिंह ने कहा कि प्रशासन को सबसे पहले यह आकलन करना चाहिए कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य बारिश के दौरान कितना पानी आता है तथा अतिवृष्टि की स्थिति में पानी की मात्रा कितनी बढ़ जाती है इसके साथ ही मौजूदा जल निकासी व्यवस्था एक निश्चित समय में कितना पानी बाहर निकाल सकती है इसका भी वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है उन्होंने कहा कि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बाढ़ नियंत्रण की प्रभावी योजना बनाई जानी चाहिए किसान नेता ने कहा कि वर्ष 1997 की बाढ़ के बाद मास्टर प्लान बनाने की बात हुई थी, लेकिन योजनाएं कागजों तक सीमित रह गईं उनके अनुसार यदि समय रहते उन योजनाओं को जमीन पर लागू किया जाता तो वर्तमान में बाढ़ के दौरान पैदा होने वाली समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता था। उन्होंने नदी और नालों में बढ़ते अतिक्रमण पर भी चिंता जताई। रामजीत सिंह ने कहा कि अतिक्रमण के कारण कई जगह नदी और नाले अपना प्राकृतिक स्वरूप खो चुके हैं जहां कभी नदी बहती थी, वहां नाले जैसी स्थिति बन गई है।

आत्मविश्वास, अनुशासन और सतर्कता से सफलता की राह आसान

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत पीएम श्री विद्यालय टंसार में छात्राओं से अधिकारियों ने किया संवाद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टंसार का निरीक्षण किया इस दौरान अधिकारियों ने कक्षा 12वीं की छात्राओं से संवाद कर उन्हें बोर्ड परीक्षा के साथ नीट एवं आईआईटी-जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने आत्मविश्वास, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच को सफलता का आधार बताया पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी हैं छात्राओं को बड़े लक्ष्य निर्धारित कर अपनी क्षमता पर विश्वास रखने और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करने की सलाह दी उन्होंने छात्राओं को व्यक्तिगत एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अनजान लोगों से सावधानी बरतें तथा अपनी निजी जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी या फोटो किसी के साथ साझा न करें सोशल मीडिया का उपयोग भी पूरी सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए किसी भी प्रकार की धमकी, साइबर अपराध या असुरक्षित स्थिति का सामना होने पर चुप न रहें, बल्कि तत्काल अभिभावकों, शिक्षकों अथवा पुलिस को जानकारी दें उन्होंने कहा कि सतर्कता और जागरूकता ही सुरक्षित समाज की मजबूत नींव है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती, यदि उसकी तैयारी सही दिशा और पूरी लगन के साथ की जाए। विद्यार्थियों को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर नियमित रूप से तैयारी करनी चाहिए उन्होंने छात्राओं से डर और झिझक को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा असफलता से सीख लेकर लगातार प्रयास जारी रखने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती, यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और मेहनत निरंतर जारी रहे इस दौरान अधिकारियों ने विद्यालय में संचालित नीट एवं आईआईटी-जेईई कोचिंग की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली कार्यक्रम में थाना प्रभारी कुसमी अरुणा द्विवेदी ने छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच की जानकारी देते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।

स्थानीय उत्पादों और महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों से सजेगा राखी मेला

23 से 25 अगस्त तक मानस भवन सीधी में होगा आयोजन, स्थानीय उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी और बिक्री

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। महिलाओं के हुनर, स्थानीय उत्पादों और स्व-सहायता समूहों की मेहनत को बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से आजीविका मिशन द्वारा तीन दिवसीय राखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला 23 से 25 अगस्त 2026 तक मानस भवन, सीधी में आयोजित होगा मेले की थीम 'स्थानीय उत्पाद, स्थानीय पहचान, आत्मनिर्भर सीधी की शान' रखी गई है। राखी मेले में जिले के महिला स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय उद्यमियों द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी एवं बिक्री की जाएगी मेले में मिलेट्स उत्पाद, जूट उत्पाद, एलईडी बल्ब, महुआ से तैयार उत्पाद, देशी अरहर दाल, बांस के उत्पाद, हैंडलूम, अचार, मूर्तियां, पंजा दरी, दोना-पत्तल सहित कई स्थानीय उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहेंगे इसके अलावा स्थानीय स्तर पर तैयार महुआ लड्डू और महुआ कुकीज जैसे उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे इन उत्पादों के माध्यम से जिले की स्थानीय उपज, पारंपरिक कौशल और महिला समूहों की उद्यमशीलता को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है मेले में आने वाले लोगों को स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता को करीब से देखने तथा सीधे उत्पादकों से खरीदारी करने का अवसर मिलेगा।

महिलाओं के हुनर को मिलेगा बाजार: राखी मेले का उद्देश्य केवल उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं है इसके माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों के हुनर को बाजार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा आजीविका मिशन ने आमजन से अपील की है कि वे राखी मेले में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करें और महिला स्व-सहायता समूहों के प्रयासों को प्रोत्साहित करें। स्थानीय उत्पाद खरीदना ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को सम्मान देने के साथ ही जिले की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमों को मजबूत करने में योगदान देगा। राखी पर्व के अवसर पर आयोजित यह मेला स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, महिला समूहों को बाजार उपलब्ध कराने और जिले की स्थानीय पहचान को नई ऊंचाई देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

यूसीसी विधेयक के विरोध में मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम सौपा ज्ञापन

मौलिक अधिकारों एवं धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण की उठाई मांग

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 के वर्तमान स्वरूप के विरोध तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के द्वारा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग रीवा के जिला अध्यक्ष मुस्ताहाक खान के नेतृत्व मे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर रीवा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन में कहा गया कि भारत की पहचान उसकी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजातीय विविधता में निहित है। संविधान निर्माताओं ने इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति-निर्देशक तत्व के रूप में रखा है, इसे मौलिक अधिकारों का स्थान नहीं दिया गया है। मुस्लिम समाज ने कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर विभिन्न समुदायों के धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करना संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकार तथा व्यक्ति की गरिमा के अधिकार को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत तथा पारिवारिक कानूनों से संबंधित धार्मिक मान्यताओं को समाप्त करने के प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई। ज्ञापन में विवाह की स्वायत्तता, व्यक्तिगत कानूनों, निकाह, तलाक की पारंपरिक व्यवस्थाओं, उत्तराधिकार एवं वसीयत से संबंधित धार्मिक प्रावधानों को एक समान व्यवस्था के अंतर्गत लाने के प्रभावों पर चिंता व्यक्त की गई।

बारिश बनी आफत : नईगढ़ी क्षेत्र में सैकड़ों घर प्रभावित, कई मकान जमींदोज,जनपद अध्यक्षया ममता कुंजबिहारी तिवारी प्रभावित बस्तियों में पहुंच कर बांटी राहत सामग्री

मीडिया ऑडीटर, नईगढ़ी (निप्र)। लगातार हुई मूसलाधार बारिश नईगढ़ी जनपद पंचायत क्षेत्र के अनेक गांवों में आफत बनकर टूटी है, कई स्थानों पर कच्चे मकान धराशायी हो गए घरों में पानी भर गया और ग्रामीणों का अनाज, खाद तथा रोजमर्रा का सामान खराब हो गया कई परिवारों के सामने रहने और भोजन तक का संकट खड़ा हो गया है सबसे अधिक चिंता उन गरीब परिवारों की है जिनके कच्चे मकान बारिश में टूट गए जानकारी के अनुसार छत्रगढ़ कला ग्राम पंचायत की सुदूर आदिवासी बस्ती में कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा और परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ा जरकटी की अनुसूचित जाति बस्ती में भी कई मकानों के गिरने या क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है मोहरिया, खुला, पहिलपार, तौरा सहित जनपद क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों में बारिश से नुकसान की सूचना है कई घरों में पानी घुसने से गृहस्थी का सामान और रखा हुआ अनाज भीगकर खराब हो गया बारिश के बाद की तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान की गंभीरता बताती हैं। कहीं मिट्टी की दीवार और खपरैल की छत पूरी तरह धराशायी दिखाई दे रही है तो कहीं ग्रामीण बारिश के बीच अपने क्षतिग्रस्त घर और सामान को संभालने में जुटे हैं जानकारी होने पर बारिश और खराब रास्तों के बीच जनपद पंचायत नईगढ़ी की अध्यक्षया ममता कुंजबिहारी तिवारी प्रभावित ग्रामीणों से मिलने पहुंचीं उन्होंने छत्रगढ़ कला की आदिवासी बस्ती में पहुंचकर स्थानीय सरपंच एवं ग्रामीणों के साथ प्रभावित परिवारों की स्थिति देखी जिन परिवारों के मकान रहने योग्य नहीं बचे थे, उन्हें सुरक्षित स्थान तथा आंगनवाड़ी भवन में ठहराने की व्यवस्था कराने की पहल की गई और प्रभावित परिवारों, विशेषकर बच्चों के लिए तत्काल भोजन की व्यवस्था भी कराई गई इसके बाद जनपद अध्यक्षया ने मोहरिया सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचीं और ग्रामीणों से नुकसान की जानकारी ली। देर शाम कोट ग्राम पंचायत पहुंचकर प्रभावित आदिवासी परिवारों से भी मुलाकात की गई और भोजन सहित तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान में अपर कलेक्टर ने कुसमी में किया निरीक्षण

फॉर्मर आईडी, राजस्व प्रकरणों और पटवारियों के कार्यों की समीक्षा, किसानों से किया सीधा संवाद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत अपर कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय ने शुक्रवार को कुसमी क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय गतिविधियों का निरीक्षण एवं समीक्षा की इस दौरान उन्होंने फॉर्मर आईडी कैंप कोडार का निरीक्षण कर उपस्थित किसानों से संवाद किया तथा फॉर्मर आईडी, खसरा एवं नक्शा से संबंधित शासन के निर्देशों की जानकारी दी उन्होंने किसानों से कहा कि फॉर्मर आईडी से जुड़ी आवश्यक कार्यवाही समय पर पूरी करें, ताकि उन्हें शासन की योजनाओं और कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो। अपर कलेक्टर ने किसानों से फॉर्मर आईडी तैयार कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से किसानों का रिकॉर्ड व्यवस्थित होने से भविष्य में विभिन्न शासकीय योजनाओं और कृषि सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया अधिक सुगम हो सकेगी उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि किसानों को फॉर्मर आईडी के उद्देश्य और उपयोगिता की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे।

तहसीलदार न्यायालय का किया निरीक्षण: इसके बाद अपर कलेक्टर ने तहसील कुसमी स्थित तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की स्थिति, न्यायालयीन कार्यवाही तथा अभिलेखों के संधारण की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए अपर कलेक्टर ने राजस्व मामलों के निराकरण में समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े प्रकरण सीधे आम नागरिकों और किसानों के हितों से जुड़े होते हैं इसलिए इनके निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के अनुसार प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। भ्रमण के दौरान अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तहसील कुसमी के पटवारियों की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।

समाजसेवी विष्णु शर्मा और प्रकाश तिवारी की बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सराहनीय पहल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में लगातार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ और घरों में पानी भरने से प्रभावित परिवारों के सामने रहने और भोजन की समस्या खड़ी हो गई है घरों में रखा खाद्य सामान और अन्य जरूरी सामग्री पानी में भीगने से खराब हो गई है ऐसे मुश्किल समय में समाजसेवी विष्णु शर्मा और प्रकाश तिवारी ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहल की है।

दोनों समाजसेवियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों से बाहर निकालकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुढ़ चौराहा में सुरक्षित स्थान पर ठहराने की व्यवस्था कराई। इसके साथ ही प्रभावित लोगों के लिए नाश्ता, भोजन और पानी की व्यवस्था भी की गई संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत प्रकाश तिवारी ने बताया कि बारिश के कारण कई लोगों के घरों में पानी भर गया है। घर का सामान खराब होने के साथ ही कई परिवारों के सामने रहने के लिए सुरक्षित स्थान और भोजन की समस्या पैदा हो गई है स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनके लिए जरूरी व्यवस्थाएं कराईं उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में समाज के सभी सक्षम लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सामूहिक जिम्मेदारी है बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए की गई इस पहल की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है।

हिम्मत से काम लें

संपादकीय

यह समय हिम्मत से काम लेने का है। घबराने की आवश्यकता नहीं है और हिम्मत से काम लें, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, कोई मलाल नहीं, हमने ही चुनकर भेजा है उन्हें, इसलिए वे हमारे हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं तथा किसी बात से विचलित न हों और हिम्मत से काम लें। गैस के दाम बढ़ गए या रोजमर्रा की बुनियादी चीजें-सुविधाएं महंगी हो गईं, डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत को पस्त न होने दें। जिस आदमी ने अपनी हिम्मत खो दी, वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। भगवान सब ठीक करता है। उस पर पूरा भरोसा रखें और हिम्मत न हारें। सरकार आये दिन अपील करती है कि जन कल्याण के लिए वह अपनी योजनाएं बना रही है, पांच वर्ष धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। छोटी-छोटी बातों को आप सलटा लें, बाकी पुल बनाने, सड़कें बनाने, कारखाने खोलने तथा अन्य जरूरी बड़े काम सरकार कर रही है। छोटे कामों में सरकार को मिलता क्या है। वह उसके लिए घाटे का सौदा है। इसलिए आप अपने घर पर मोर्चा संभालें तथा सरकार को देश चलाने दें। इधर सरकार ने हर काम के लिए ब्याज के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का नेक कार्य शुरू कर दिया है। आप लोन लेकर अपनी समस्याओं को समाधान तक पहुंचाएं, बाकी आप कमाएं-खाएं तथा हिम्मत से काम लेकर ऋण की अदायगी करें। पानी, बिजली और टेलीफोन का बिल ज्यादा आ रहा है या गेहूं महंगा हो रहा है या आलू प्याज के भाव आसामन छू रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है और हिम्मत से काम लें। आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। देखने में यह आ रहा है कि आदमी जरा सी परेशानी से घबरा उठता है, अरे भाई इसमें घबराने की क्या बात है। मनोबल से काम लें और हर मुश्किल से जूझने को संकल्प, फिर देखिये मुश्किलें कितनी आसान हो जाती हैं। आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या आप उसे पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसे बाल मतदूरी में लगा दो, घर की आय बढ़ेगी और आपकी हिम्मत अलग से बढ़ेगी। स्कूल महंगे होंगे तो आप करेंगे क्या? बच्चे को दिशा दीजिये। उसको लेकर बड़े-बड़े सपने न संजोयें। सपने पूरे नहीं होने पर, आदमी भीतर से टूटता है। वैसे भी घबराने की क्या बात है, पत्नी को भी प्राइवेट फैक्टरी में काम करने भेज दें। वह भी कुछ न कुछ लेकर आएगी तो इससे आप में हिम्मत का संचार होगा तथा राष्ट्रीय आय में भी इजाफा होगा। मैंने बाल मजदूरी की बात की, माना बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध है, लेकिन इस पापी पेट के लिए मेहनत-मजदूरी करना मैं गलत नहीं मानता। वैसे भी सरकार ने बाल मजदूरी कराने वालों को आज तक कब और कितना दण्डित किया है। आपने बच्चे को पढ़ा दिया तो वह घर का रहेगा न घाट का। इसलिए उसे नासमझी की उम्र में ही काम पर लगा देना समझदारी है। पत्नी का टाइम टेबल ऐसा सैट करो कि सुबह तीन बजे उठकर घर का काम-काज निपटा ले और सुबह सात बजे काम पर निकल जाए। शाम को आकर फिर अपना चौका बर्तन संभाल ले। रात ग्यारह बजे तक अपना काम निपटा लीजिये, देखिये आपकी गृहस्थी कितनी खुशहाल होगी। लेकिन यह होगा हिम्मत से। हाथ पर हाथ धरे रखने से बात बनती नहीं, बिगड़ती है। आप कमाएं, बच्चे कमाएं और पत्नी कमाए, बताइये घर में क्या कमी रह गई।

सड़क पर पैदल चलना भी मौलिक अधिकार, फिर फुटपाथ क्यों बेहाल?

सड़क पर पैदल चलना मौलिक अधिकार है, लेकिन आज भारत के कई शहरों में पैदल चलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल, आज भी बहुत से शहरों में फुटपाथ या तो बने ही नहीं हैं, या उन पर अतिक्रमण, पार्किंग और निर्माण सामग्री के कारण लोगों के चलने की जगह नहीं बचती। ऐसे में यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब किसी व्यक्ति के पास सड़क पर सुरक्षित रूप से पैदल चलने की जगह ही नहीं है, तो उसे वास्तव में आवागमन की आजादी कैसे मिल सकती है?

उक्त संदर्भ में यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ही यानी कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा है कि सुरक्षित और निर्धारित पैदल मार्ग पर चलना भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत आवागमन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। वास्तव में, यह मामला उस दुखद घटना से जुड़ा हुआ था, जिसमें पांच साल के एक बच्चे की सड़क पर टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहां न फुटपाथ था और न ही सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज कई भारतीय शहरों में फुटपाथ पर अतिक्रमण, टूटे या गायब फुटपाथ, सड़क पार करने के लिए अपर्याप्त क्रॉसिंग, तेज रफ्तार वाहन और यातायात नियमों का उल्लंघन पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ाते हैं और हमारे देश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती है। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में 35,221 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, जो कुल सड़क दुर्घटना मौतों का 20.4% थी।सच तो यह है कि आज पर्याप्त पैदल यात्री बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है?। यहां पाठकों को बताता चलूं कि फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव मुख्यतः राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के दायरे में आता है, इसलिए सरकारों और संबंधित निकायों को इन पर ध्यान देना चाहिए। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वैसे विश्व में सड़क की गुणवत्ता, फुटपाथ, पैदल पार-पथ, ट्रैफिक नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मामलों में नीदरलैंड को दुनिया के सबसे अच्छे उदाहरणों में गिना जाता है। सच तो यह है कि नींदरलैंड पैदल चलने के लिए दुनिया में एक अग्रणी देश है, जहां पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए अलग एवं सुरक्षित मार्ग, कम गति वाले क्षेत्र और बेहतर सड़क डिजाइन उपलब्ध हैं। नींदरलैंड के बाद डेनमार्क विशेषकर कोपेनहेगन में पैदल यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित फुटपाथ, क्रॉसिंग और ट्रैफिक-शांत क्षेत्र हैं। वहीं पर स्वीडन विश्व में कम पैदल मृत्यु दर और मजबूत सड़क-सुरक्षा व्यवस्था के कारण अग्रणी देशों में शामिल है।नॉर्वे(यूरोप में) तथा फिनलैंड भी पैदल मार्गों और सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था के मामले में विश्व में अहम् और महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

हाल फिलहाल, यहां यह कहना चाहूंगा कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क पर पैदल चलने के संदर्भ में जो फैसला दिया है,इस फैसले का सीधा सा संदेश यही है कि सरकार और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि ये लोगों को सुरक्षित फुटपाथ और सड़क पार करने की उचित सुविधा उपलब्ध कराएं। वास्तव में,सच तो यह है कि नगर निगम, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण और पंचायतों को आगे आकर इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करना होगा।बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो, आंकड़े हमारी चिंताएं बढ़ाते हैं। यह बहुत ही दुखद है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक लोग पैदल यात्री होते हैं। कई शहरों में फुटपाथ टूटे हुए, संकरे, असुरक्षित या लगातार बाधित पाए गए हैं। यानी समस्या केवल फुटपाथ बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, चौड़ा, समतल और सभी के लिए सुगम बनाने की है। वास्तव में,इसके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग न हो, वहां पर पर्याप्त रोशनी हो, सड़क पार करने के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग बने और दिव्यांगजनों के लिए रैंप तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। सड़क की खुदाई या निर्माण कार्य के दौरान भी पैदल यात्रियों के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए।

एकाकी होता जीवन का संध्या काल

यह समाचार सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला था कि सोनीपत, हरियाणा के वृद्धाश्रम में रह रहे एक वयोवृद्ध पिता की मृत्यु के बाद उनकी तीनों बेटियों या नाती-नातिनों में से कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। बेटियों ने वीडियो काल पर अंतिम संस्कार करना चुना। दिवंगत पिता प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया और उनका विवाह कर पिता होने का दायित्व निर्वाह किया, फिर भी बेटियां न तो उनके अंतिम संस्कार में आईं और न ही तेरहवीं में। पिछले कुछ वर्षों में वृद्ध माता-पिता अपनी संतानों द्वारा अपमानित, उपेक्षित और तिरस्कृत हुए। बुजुर्ग भरा-पूरा परिवार और संसाधन होने के बाद अपने मकानों या वृद्धाश्रमों में एकाकी जीवन जीने को अभिशप्त हैं। यह लगातार स्वार्थी, यांत्रिक और संवेदनहीन होते जा रहे समकालीन समाज के रोबोटीकरण का प्रतिबिंब है।

प्रो. रसाल सिंह

तीन बेटियों के अंतिम संस्कार में शामिल न होने को केवल अमानवीय कहकर नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कुछ ठोस सामाजिक और आर्थिक कारण काम कर रहे हैं। पहला है-समय की पुनर्परिभाषा। आज के शहरी जीवन में समय को उत्पादकता से जोड़ दिया गया है। हर गतिविधि का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि उससे करियर या आय में कितनी वृद्धि होगी। अंतिम संस्कार इस पैमाने पर खरा नहीं उतरता। उससे कोई स्वार्थसिद्धि या लाभ नहीं होताढ्ढ इसलिए वह महत्वहीन हो जाता हैढ्ढ दूसरा कारण है भावनात्मक दूरी। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक माता-पिता से नहीं मिलता तो उनके प्रति लगाव कम हो जाता है। मृत्यु की जानकारी एक निर्जीव सूचना बनकर रह जाती है, एक आघात नहीं। तीसरा कारण है सामाजिक स्वीकृति में बदलाव। पहले यदि कोई संतान माता-पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती थी तो उसे अपराध-बोध और एक किस्म के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। आज ऐसे व्यवहार को 'व्यस्त जीवन जनित विवशता' कहकर सामान्यीकृत सा कर दिया गया है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में बेटियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे माता-पिता की अधिक देखभाल करेंगी, पर अब बेटियां भी नौकरी के कारण उसी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का हिस्सा बन जा रही हैं, जिसमें पुरुष पहले से थे। उनका व्यवहार भी बेटों जैसा होता जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि बेटियां संवेदनहीन हो गई हैं, बल्कि यह है कि बाजार आधारित आर्थिकी ने स्त्री और पुरुष, दोनों को उत्पादक और उपभोक्ता में अवमूल्यित कर दिया है। पिछले कुछ दशकों में संयुक्त परिवार टूटे हैं और एकल परिवार का चलन बढ़ा है। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लोगों का पलायन/विस्थापन हुआ है। भौगोलिक दूरी का सीधा असर बुजुर्ग माता-पिता पर पड़ा है। उनके पास दो विकल्प बचे हैं-या तो अकेले रहें या वृद्धाश्रम में। दोनों ही स्थितियों में उनकी देखभाल और भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं। अबाध स्वतंत्रता, निजता की चाह और असीम भौतिकता ने भी परिवारों की नींव को हिलाया है। जब पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, तो वृद्धाश्रम को एक व्यावहारिक समाधान मानकर बुजुर्गों को निर्वासित कर दिया जाता है। प्रारंभ में महीने में मिलने का वादा होता है। फिर यह अवधि बढ़ती जाती है। फोन पर बात भी औपचारिक होती जाती है। धीरे-धीरे बुजुर्ग बच्चों के जीवन से निष्कासित हो जाते हैं। राष्ट्रीय वृद्धजन आयोग और कुछ स्वतंत्र संस्थाओं के सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में 15 प्रतिशत से अधिक वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं। महानगरों में यह प्रतिशत 25 के आसपास है। वृद्धाश्रमों में रहने वाले 60 प्रतिशत से अधिक लोगों के बच्चे देश के भीतर ही रहते हैं। वृद्धाश्रमों में प्रवेश लेने वाले 40 प्रतिशत बुजुर्ग उच्च और मध्यम वर्ग से हैं। स्पष्ट है इस समस्या का मूल कारण आर्थिक तंगी से ज्यादा आत्मकेंद्रित एवं उपयोगितावादी मूल्यचेतना और पाश्चात्य जीवनशैली है। आज अंतिम संस्कार के लिए 'लास्ट जर्नी' जैसी सेवा प्रदाता कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी हैं। यदि आज की पीढ़ी अपने माता-पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो आने वाली पीढ़ी भी कल यही करेगी। यह एक सामाजिक दुष्चक्र है। परिवार नामक संस्था भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता रही है। उसे बचाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि संगठन 'कुटुंब प्रबोधन' जैसे अभियान चलाकर इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। नीतिगत स्तर पर सरकार को वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए होम हेल्थ केयर, डे केयर सेंटर और सामुदायिक केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने माता-पिता की देखभाल के लिए 45 दिन की छुट्टियां देने का प्रस्ताव किया है। अन्य कंपनियों और प्रतिष्ठानों को भी कर्मचारियों को 'चाइल्ड केयर लीव' और 'पैरेंट्स केयर लीव' देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें ऐसा करने पर टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना होगा। हमें नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भाव सिखाना होगा।

जवाबदेही से दूर होते जनप्रतिनिधि

राजकुमार सिंह

प्रति मिनट की कार्यवाही पर करीब ढाई लाख रुपये के खर्च की बर्बादी के पुराने आंकड़े दोहराते हुए संसद की गिरती उत्पादकता पर फिर चिंता जताई जा रही है। मानसून सत्र में मात्र 19 प्रतिशत कामकाज ही हो पाया और 173 कार्य घंटे बर्बाद हो गए। दो महत्वपूर्ण विधेयक मात्र 14 मिनट की चर्चा में पारित कर दिए गए तो 11 बिना किसी चर्चा के। जाहिर है कि संसद में काम कम हुआ और हंगामा ज्यादा तो उसके लिए कोई जिम्मेदार भी होना ही चाहिए। हमारी संसदीय राजनीति में हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की परंपरा रही है। बेशक हंगामे की शुरुआत अक्सर विपक्ष की ओर से ही होती है, मगर अकारण तो कुछ भी नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान उसके कारणों के निवारण की मांग करता है, लेकिन हम कारणों से ही मुंह चुरा लेने के अभ्यस्त हो चले हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष की भूमिकाएं बदलते ही भाव-भंगिमाएं बदल जाना गैर-जिम्मेदार और अवसरवादी राजनीति ज्यादा है। 2014 से पहले नेता-प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और अरुण जेटली सदन चलाना सत्तापक्ष की जिम्मेदारी तथा संसदीय गतिरोध को भी संसदीय राजनीति का संवैधानिक उपकरण बताते थे, पर सत्ता पाने के बाद भाजपा का सोच बदल गया। तब संसदीय गतिरोध के लिए भाजपा को कठघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस अब अपनी वैसी ही भूमिका को सर्वथा लोकतांत्रिक ठहरा रही है। संसदीय गतिरोध और उसके जरिये सड़क की राजनीति का एजेंडा तय करने की प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन उसका लगातार बढ़ते जाना खतरनाक है। पहले जो विरोध वैचारिक या मुद्दा आधारित होता था, अब वह दलगत रंजिश में बदल गया लगता है। इसी कटुता का परिणाम और प्रभाव है कि एक-दूसरे पर टिप्पणी करते हुए भाषाई मर्यादा भी तार-तार की जा रही है। संसद के मानसून सत्र जैसा हंगामा पहली बार नहीं हुआ। नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्वकाल में हर्षद मेहता कांड पर भी संसद में ऐसे ही दृश्य देखे गए थे। मनमोहन सिंह के समय टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले पर संसद कई दिनों तक ठप रही थी। तब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में। वह राष्ट्र हित था और यह राष्ट्र विरोध। ऐसा अतार्किक सोच दलों-नेताओं का हो सकता है, जनता का नहीं। इस बार तो हंगामे का संकेत सत्र की शुरुआत के साथ ही मिल गया था। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र एवं युवा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। मानसून सत्र के पहले ही दिन 20 जुलाई को संसद मार्च का एलान भी किया जा चुका था। सरकार की विलंबित सक्रियता का भी परिणाम रहा कि संसद मार्च के दौरान हिंसा हुई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद बाद के घटनाक्रम और उसके चलते हुए राजनीतिक नुकसान से नहीं बचा जा सका। सरकार की उसी नाकामी से विपक्ष के हाथ ऐसा मुद्दा लग गया, जिसने सत्तापक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया। जब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव चंद महीने ही दूर हैं, तब विपक्ष उस मुद्दे को हाथ से कैसे चले जाने देता, जिसने उसे उस 'जेन जी' के हितों का चैंपियन बनने का मौका दे दिया, जो आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है और जिसका समर्थन हाल तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बड़ी ताकत रही? फिर एक इस्तीफे पर ही न रुक जाने की आक्रामक राजनीति भी विपक्ष ने भाजपा से ही सीखी है। मनमोहन सिंह के दौर में तमाम आरोपों के आधार पर ही भाजपा ने एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे करवाए थे। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को आना ही था। संसदीय गतिरोध में भी समाधान का रास्ता निकालने की कवायद सदन के सभापति और संसदीय कार्य मंत्री कर सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इन दोनों के भी विपक्ष से संबंध सहज नहीं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में शुरू हुई संसद में 'हल्ला ब्रिगेड' की खतरनाक परंपरा तोड़ने की जरूरत किसी ने भी नहीं महसूस की।

आज भी सदन में दोनों ही ओर हंगामेबाजों की कमी नहीं, लेकिन यदि संसदीय कार्य मंत्री भी उसी ब्रिगेड का सदस्य बनते दिखें तो विपक्ष से संवाद की पहल कौन करेगा? पिछली लोकसभा में विपक्षी सांसदों के रिकार्ड निलंबन के बाद से स्पीकर ओम बिरला भी विपक्ष का विश्वास लगभग खो चुके हैं। सत्रावसान के बाद उनकी चाय पार्टी का भी विपक्ष ने बहिष्कार किया। जाहिर है, यह सब संसदीय लोकतंत्र की सुखद तस्वीर पेश नहीं करता, लेकिन क्या आपको किसी के चेहरे पर शिकन भी नजर आती है? नहीं, क्योंकि संसद चलने न चलने से न सत्तापक्ष को फर्क पड़ता है और न ही विपक्ष को। बिना बहस और जवाबतलबी के विधेयक पारित हो जाएं तो सत्तापक्ष के लिए इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है? दोनों ही सदनों में विपक्ष को भी संसद से बाहर सड़क और चुनाव की राजनीति के लिए अपने मुद्दों को धार देने का मौका मिल ही रहा है। दोनों ही एक-दूसरे को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, पर कौन कितना लोकतांत्रिक है, वह जनता बखूबी जानती है। दोनों सदनों के लगभग साढ़े सात सौ सांसदों के वेतन-भत्तों और सुख-सुविधाओं पर भी तो करदाताओं की गाढ़ी कमाई ही खर्च होती है।

स्कूलों के दरवाजे बंद, सवालों से क्यों डर रहीं हैं सरकारें?

जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों की झड़प और मारपीट की घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सीजेपी का आरोप है, इस विरोध के पीछे भाजपा समर्थक थे। उपलब्ध रिपोर्ट में भाजपा ने दावा किया है, ग्रामीणों ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध करते हुए उनके साथ मारपीट कर उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। मुद्दा केवल यह नहीं है, जयपुर में किसने किसे पीटा। असली प्रश्न यह है, सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति देखने, उसकी तस्वीर लेने और उसे जनता के सामने रखने से किसे डर लग रहा है?

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी के लिए प्रधानाचार्य की अनुमति अनिवार्य करने का आदेश क्यों सामने आया है? छात्रों से बातचीत करने पर क्यों रोक लगाई जा रही है? आदेश पर सरकार का तर्क बच्चों की सुरक्षा, निजता और विद्यालय में अनावश्यक व्यवधान को रोकने की बात कही जा रही है। यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब जेन-अल्फा के स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी मांग को लेकर कई राज्यों के कई स्थानों पर सड़क पर उतरे हैं। जब सीजेपी एवं अन्य राजनीतिक दल सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर अभियान चला रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता और सच को छुपाने को लेकर सवाल उठते हैं।

उत्तर प्रदेश में भी बिना अनुमति सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स के प्रवेश पर रोक की खबर है। वहां भी प्रशासन का तर्क सुरक्षा और पढ़ाई में व्यवधान बताया गया है। यह कहना कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें अपनी कमियां छिपाना चाहती हैं। पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, यह सवाल जरूर महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठनों की सक्रियता को इसी व्यापक राजनीति से जोड़ा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी

परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा से जुड़े हुए अनुवांशिक संगठन लंबे समय से विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करके वहां हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन पर इस तरीके की कोई रोक-टोक नहीं है। यदि कोई संगठन स्कूल-कॉलेजों की समसस्यों को देखकर और सुनकर समाधान के लिए प्रशासन और सरकार के सामने लाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में उसका स्वागत होना चाहिए। यही अधिकार विपक्षी दलों और स्वतंत्र सामाजिक संगठनों को भी मिलना चाहिए। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिक्षा संस्थान किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं हैं। वे जनता के पैसे से चलते हैं। वहां पढ़ने वाले बच्चे समाज के भविष्य हैं। स्कूल की टूटी छत, जर्जर भवन, शिक्षक की कमी, शौचालय, पेयजल, प्रयोगशाला या पाठ्यपुस्तकों की कमी की किसी भी समस्या को उजागर करने वाला व्यक्ति राजनीतिक विरोधी हो सकता है। कम उम्र के छात्रों की समस्या को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। ऐसी स्थिति में कम उम्र के छात्रों के अधिकार को कैसे छीना जा सकता है।

जयपुर की घटना इसलिए गंभीर है, क्योंकि सीजेपी शिक्षा एवं परीक्षा संबंधी मुहिम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है। राजस्थान में प्रशासन, पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं से टकराव की खबरें सामने आना चिंता का कारण है। कुछ दिन पहले अलवर में जर्जर स्कूल को लेकर सीजेपी अभियान के बाद सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने की रिपोर्ट आई थी। इसका अर्थ यह है कि दबाव बनाने वाली सक्रियता से व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। राजनीति का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग मुद्दों पर नहीं, बल्कि एक-दूसरे को मैदान से हटाने के लिए होने लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसी संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है? तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यदि सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश किया या स्थानीय लोगों को आपत्ति थी, उसके लिए कानून के तहत शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। भीड़ को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहे जेन जेड और जेन अल्फा से जुड़े आंदोलनों को लेकर भी राजनीतिक दलों में नई रणनीतियां बनना शुरू कर दी हैं। छात्र एवं युवा अब आश्वासन राजनीतिक भाषण नहीं सुनता है। वह अपनी समस्याओं का समाधान निश्चित समय सीमा पर चाहता है। वह सवाल का जवाब भी तुरंत चाहता है। आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, फीस, डिजिटल अधिकार और सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता बड़े राजनीतिक मुद्दे बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा और संघ परिवार यदि युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सक्रियता बढ़ाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विपक्षी दल भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष को समान अधिकार प्राप्त हैं। मुकाबला होना चाहिए,विचारों मे हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सरकार के लिए सबसे अच्छा रास्ता स्कूलों के दरवाजे बंद करना नहीं, स्कूलों की समस्याओं को जवाबदेही के साथ सुलझाना और पारदर्शी बनाना है। कोई भी कैमरा वहां की व्यवस्था की सच्चाई को दिखाएगा, तो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जवाबदेह होंगे। सरकार को इसमें शर्मिंदा होने के स्थान पर, जिन अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि व्यवस्थाओं में सुधार हो। बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए नियम बनाना उचित हो सकता है, मगर स्वतंत्र निरीक्षण, पत्रकारिता और जनप्रतिनिधियों की निगरानी के लिए स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। जयपुर मैं जो घटना हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच से सच सामने आना चाहिए।

इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका है, तो उन पर कार्रवाई हो, यदि किसी पक्ष ने कानून तोड़ा है, उसके खिलाफ समान कार्रवाई हो। लोकतंत्र में सत्ता की असली ताकत विरोधी आवाज को दबाने में नहीं, बल्कि विरोधी आवाज सुनकर व्यवस्था को बेहतर बनाने में है। सरकारी स्कूलों के दरवाजे बच्चों के लिए खुले रहने चाहिए। उनकी समस्याओं पर सवाल पूछने वालों के लिए भी लोकतांत्रिक रास्ते भी खुले रहने चाहिए। सवाल स्कूल का नहीं छात्रों के मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। यदि 16 साल से कम उम्र के छात्र सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यह सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण है। वर्तमान का बच्चा अपनी जरूरत के लिए इसी तरह का प्रदर्शन अपने घर पर भी करता है और अब वह स्कूल में उसकी जो जरूरत है उन मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतर रहा है तो इस मामले को दबाया नहीं जा सकता है। बच्चे तो बच्चे हैं, जिद करेंगे, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी।

पुलिसिंग में नवाचार से बढ़ रहा जनता का विश्वास, सुरक्षा और सुधार का संदेश

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा पुलिसिंग को अधिक संवेदनशील, मानवीय और जनोन्मुखी बनाने के लिए विभिन्न जिलों में अभिनव पहल की जा रही है। बड़वानी, इंदौर और शाजापुर पुलिस के प्रयासों में सुधारात्मक पुलिसिंग, बच्चों की सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है बड़वानी में पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल के नेतृत्व में थानों की हवालातों की दीवारों पर प्रेरक चित्र और संदेश लगाए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि और महात्मा बुद्ध की कहानियों के जरिए आत्मचिंतन और सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया जा रहा है थानों में महिलाओं के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क बच्चों के लिए वात्सल्य कक्ष फीडिंग रूम और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है इंदौर पुलिस की 'स्व-रक्षा बंधन पहल के तहत करीब 2 हजार विद्यार्थियों और 5 हजार अभिभावकों तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाया जा रहा है बच्चों को जेब्रा क्रॉसिंग, हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक सिग्नल के नियमों की जानकारी दी जा रही है।

बहनों की तरक्की, परिवार की शान - विष्णु भैया का यही अभियान

महतारी वंदन योजना से बढ़ी रक्षाबंधन की खुशी, 30वीं किस्त पाकर नंदिनी ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना जिले की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आधार बन रही है इसी योजना से लाभान्वित मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम हर्री निवासी नंदिनी राय के लिए इस बार रक्षाबंधन का त्योहार विशेष खुशी लेकर आया है नंदिनी राय को महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत उन्हें अब तक कुल 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सहायता से त्योहार की तैयारियों में काफी मदद मिली है। वह इस वर्ष योजना से प्राप्त राशि का उपयोग राखी और मिठाई खरीदने में करेंगी नंदिनी बताती हैं कि त्योहारों के समय घर में अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। ऐसे समय में योजना के तहत मिलने वाली राशि छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में काफी सहायक होती है इससे परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव कम होता है और त्योहार की खुशियां भी बनी रहती हैं हर महीने की सहायता से परिवार को आर्थिक संबल नंदिनी राय का कहना है कि महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 1,000 रुपये की राशि महिलाओं के लिए नियमित आर्थिक सहारा है। इस राशि का उपयोग महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार बच्चों की आवश्यकताओं, घरेलू सामान, स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा त्योहारों से जुड़े खर्चों में कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब योजना की राशि से वे अपनी जरूरतों में स्वयं भी योगदान दे पा रही हैं इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी भी बढ़ी है नंदिनी के अनुसार महतारी वंदन योजना की राशि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सकता है घर की दैनिक जरूरतों से लेकर बच्चों की आवश्यकताओं तक यह सहायता कई अवसरों पर काम आती है उनका कहना है कि महिलाओं के हाथ में नियोजित आर्थिक सहायता होने से परिवार की आर्थिक व्यवस्था को संभालने में भी मदद मिलती है छोटी राशि होने के बावजूद लगातार मिलने वाली सहायता का असर परिवार के दैनिक जीवन पर दिखाई देता है योजना का लाभ मिलने पर नंदिनी राय ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा मुझे महतारी वंदन योजना की राशि मिलने से बहुत खुशी है रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने पर मैं इससे राखी और मिठाई खरीदूंगी यह राशि हमारे बच्चों और घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में भी बहुत काम आती है मैं मुख्यमंत्री विष्णु देव भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं आर्थिक संबल से बढ़ रहा महिलाओं का आत्मविश्वास महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार भी बन रही है नंदिनी राय जैसी महिलाएं इस राशि का उपयोग अपनी जरूरतों और परिवार की खुशहाली के लिए कर रही हैं। योजना से महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में अपनी भूमिका बढ़ाने और परिवार की जरूरतों में स्वयं योगदान देने का अवसर मिल रहा है नंदिनी की कहानी यह दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाला नियमित आर्थिक सहयोग किस तरह आम परिवारों के दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो सकता है रक्षाबंधन से पहले मिली 30वीं किस्त ने उनके लिए त्योहार की तैयारियों को आसान बनाया और परिवार में खुशियों का एक नया रंग जोड़ा बहनों की तरक्की, महतारी वंदन योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का यही अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर परिवार की मजबूत कड़ी बना रहा है।

BJP विधायक प्रीतम लोधी का आरोप- महिलाओं को भेजकर फंसाने की साजिश, बेटे को भी निशाना बनाने का दावा

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने दावा किया कि उन्हें दुष्कर्म के मामले में फंसाने के लिए महिलाओं को उनके पास भेजा जाता है। पहले महिलाओं से बहस या विवाद कराने की कोशिश होती है और इसके बाद बातचीत का वीडियो बनाकर उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रची जाती है विरोधी सीधे उनके पास नहीं आते बल्कि पिछोर के डाकबंगले में महिलाओं को भेजते हैं उनका आरोप है कि महिलाओं को ऐसी बातें कहने के लिए उकसाया जाता है, जिससे वह प्रतिक्रिया दें और बाद में उसी बातचीत या विवाद का वीडियो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लोधी ने दावा किया कि इस तरह उन्हें दुष्कर्म के मामले में फंसाने की तैयारी की जा रही है प्रीतम लोधी ने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ अक्सर एक व्यक्ति मोबाइल लेकर आसपास मौजूद रहता है। विधायक के मुताबिक उसका उद्देश्य बातचीत या विवाद को रिकॉर्ड करना होता है। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं के व्यवहार से उन्हें कथित साजिश का अंदेशा हुआ। उनका दावा है कि उन्हें बहकाकर विवाद खड़ा करने और बाद में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है विधायक ने अपने बेटे राकेश लोधी को भी निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विरोधी इसी तरह की रणनीति अपनाकर बेटे को भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बेटे को ऐसे मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी। विधायक ने यह भी दावा किया कि डाकबंगले पर पहुंची एक महिला ने उन्हें कथित साजिश की जानकारी दी थी हालांकि, विधायक के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित विरोधियों का पक्ष सामने नहीं आया है दरअसल, 14 अगस्त की रात खनियाधाना में अहिल्याबाई की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद पाल-बघेल समाज में आक्रोश है। इसी के विरोध में 20 अगस्त को समाज की ओर से आक्रोश आंदोलन आयोजित किया गया था विधायक प्रीतम लोधी भी इसमें शामिल हुए और मंच से समाज को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर लगाए गए इन आरोपों का जिक्र किया।

कृषि से मत्स्य पालन तक का सफर : अरविंद सिंह ने इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग से खड़ी की 8 लाख से अधिक वार्षिक आय की मिसाल

वैज्ञानिक मत्स्य पालन, मछली बीज उत्पादन और हैचरी से बढ़े आय के स्रोत, 15 से अधिक लोगों को मिला रोजगार

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि के साथ मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं इसका प्रेरक उदाहरण मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम ताराबहरा निवासी मत्स्य कृषक अरविंद सिंह हैं जिन्होंने पारंपरिक कृषि से आगे बढ़कर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग को अपनाया और अपने फार्म को बहुआयामी आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित किया। आज उनके फार्म पर मत्स्य पालन के साथ मछली बीज उत्पाद हैचरी सूकर एवं कुक्कुट पालन जैसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इनसे उन्हें लगभग 8 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, वहीं 15 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिल रहा है अरविंद सिंह बताते हैं कि मत्स्य पालन शुरू करने से पहले उनकी आय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। मेहनत और लागत के अनुरूप अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उन्होंने आय के अतिरिक्त साधनों की तलाश शुरू की इसी दौरान उन्होंने मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया और धीरे-धीरे अपने फार्म को इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मॉडल में विकसित किया आज उनके फार्म पर 5-6 नर्सरी तालाब, 2 ब्रुडर तालाब तथा स्टाकिंग तालाब संचालित हैं नर्सरी तालाबों में मत्स्य बीजों का प्रारंभिक पालन ब्रुडर तालाबों में प्रजनन योग्य मछलियों का रख-रखाव तथा स्टॉकिंग तालाबों में मछलियों का पालन किया जाता है। इस वैज्ञानिक व्यवस्था से उत्पादन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हुई है हैचरी और मछली बीज उत्पादन से बढ़े आय के स्रोत अरविंद सिंह के फार्म पर स्वयं की मत्स्य हैचरी भी है, जहां विभिन्न प्रजातियों के मत्स्य बीज तैयार किए जाते हैं। यहां इंडियन मेजर कार्प (IMC), एक्सोटिक कार्प सहित अन्य प्रजातियों का पालन किया जाता है पंगासीयस मछली के स्पिनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है इसके साथ ही उन्होंने कतला मछली में क्रॉस ब्रीडिंग का प्रयास कर मत्स्य उत्पादन में नई संभावनाएं तलाशने की दिशा में कदम बढ़ाया है फार्म पर पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और मछलियों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए आवश्यक प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

मदहा वॉटरफॉल में विकास की नई रोशनी, सोलर हाई मास्ट से बढ़ी पर्यटन सुविधाएं

डीएमएफ से 10.76 लाख रुपये की लागत से स्थापित 2 सोलर हाईमास्ट, रात में सुरक्षित हुआ पर्यटन क्षेत्र

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। सुदूर वनांचल क्षेत्रों में विकास की पहुंच को मजबूत करने के साथ पर्यटन स्थलों को सुविधायुक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसी क्रम में विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत बेनीपुरा स्थित रमदहा वॉटरफॉल में डीएमएफ मद से 10 लाख 76 हजार रुपये की लागत से 2 सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापित किए गए हैं सौर ऊर्जा से संचालित इन संयंत्रों के शुरू होने से पर्यटन क्षेत्र में रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हुई है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा के साथ सुरक्षा भी मिली है र्यटन क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित रमदहा वॉटरफॉल प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और जलप्रपात के कारण जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है सुदूर वनांचल में स्थित होने के कारण यहां पहले पारंपरिक विद्युत सुविधा

उपलब्ध नहीं थी सूर्यास्त के बाद पर्यटन स्थल और आसपास का क्षेत्र अंधकारमय हो जाता था, जिससे रात्रिकालीन आवागमन में लोगों को कठिनाई होती थी पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने की पहल की क्रियान्वयन एजेंसी क्रेडा के माध्यम से लगाए गए दोनों सोलर हाईमास्ट आसपास के लगभग 50-50 मीटर क्षेत्र को रोशन कर रहे हैं रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था से पर्यटन स्थल पर आने-जाने वाले लोगों को रास्ते और आसपास का क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देने लगा है वन क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवरों की मौजूदगी को देखते हुए प्रकाश व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है इससे अंधेरे के कारण होने वाली परेशानियों और जोखिमों को कम करने में मदद मिल रही है स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहले शाम होते ही क्षेत्र में अंधेरा छा जाता था, लेकिन अब सोलर हाई मास्ट की रोशनी से आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। पर्यटकों को भी बेहतर वातावरण मिल रहा है रमदहा वॉटरफॉल में सोलर हाईमास्ट की स्थापना केवल प्रकाश व्यवस्था का विस्तार नहीं बल्कि दूरस्थ वनांचल में स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास का उदाहरण है जहां पारंपरिक बिजली पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सीवर खुदाई के दौरान फिर फूटी मुख्य पेयजल लाइन, 35 वार्डों में सप्लाई प्रभावित ठेकेदार पर FIR के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के दौरान एक बार फिर मुख्य पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गुरुवार देर रात मीनाक्षी चौक पर अंडरग्राउंड पाइप डालते समय इंटेकवेल से फिल्टर प्लांट तक जाने वाली मुख्य पेयजल पाइपलाइन में बड़ा लीकेज हो गया पाइप फूटने से मौके पर बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया और शहर के करीब 35 प्रतिशत हिस्से में शुक्रवार को पेयजल सप्लाई प्रभावित रही रसूलिया क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा असर बताया गया है पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद फिल्टर प्लांट की पानी सप्लाई रोकनी पड़ी। नगर पालिका ने प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर और ट्यूबवेल के

माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की है अधिकारियों के मुताबिक, लाइन की मरम्मत के बाद नियमित जलापूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है शहर में सीवरेज लाइन और अमृत-2.0 योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम करीब चार साल से जारी है स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में लापरवाही के कारण कई बार पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है बार-बार पानी की पाइपलाइन टूटने से लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने नगर पालिका सीएमओ वैभव देशमुख को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए इसके बाद नगर पालिका ने कोतवाली थाने में शिकायत आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है स्थानीय लोगों के मुताबिक, पाइपलाइन बिछाने के बाद कई जगह मिट्टी डालकर काम अधूरा छोड़ दिया जाता है। बारिश होने पर इन स्थानों पर कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे वाहन फिसलने और लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है मीनाक्षी चौक पर खुदाई के कारण आवागमन में भी परेशानी हो रही है नगर पालिका के पेयजल प्रभारी मुकेश जैन ने बताया कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से फिल्टर प्लांट की सप्लाई प्रभावित हुई है प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों और ट्यूबवेल के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। संबंधित कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है।

बेटी को पूरी किताबें नहीं मिलीं तो जागरूकता यात्रा की मांग, अनुमति न मिलने पर टंकी पर चढ़ा युवक

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के पिछोर में एक युवक ने बेटी को स्कूल से पूरी किताबें नहीं मिलने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार को लेकर 22 दिन की जागरूकता यात्रा निकालने की अनुमति मांगी प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसके पास पेट्रोल की बोतल होने की सूचना से मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और उसे नीचे उतारने के लिए समझाइश दी मनपुरा गांव निवासी दिनेश सगर का कहना है कि उसकी बेटी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती है। चालू शैक्षणिक सत्र में उसे स्कूल से पूरी किताबें नहीं मिलीं। दिनेश के

मुताबिक, जब उसकी बेटी को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो गांव के दूसरे बच्चों को भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं इसी को लेकर उसने गांव-गांव जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के प्रति लोगों को जागरूक करने की योजना बनाई थी दिनेश ने 19 अगस्त को पिछोर एसडीएम को आवेदन देकर 20 अगस्त से 22 दिन की यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगी थी उसने यात्रा के दौरान स्कूलों अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को देखने तथा शिक्षण व्यवस्था और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों को सामने लाने की बात कही थी दिनेश ने आवेदन में कहा था कि यात्रा के दौरान कोई असंवैधानिक गतिविधि नहीं की जाएगी साथ ही अनुमति नहीं मिलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी अनुमति नहीं मिलने के बाद वह पानी की टंकी पर चढ़ गया पिछोर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार के अनुसार, युवक गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे टंकी पर चढ़ा पुलिस लगातार उसे समझाने का प्रयास कर रही है युवक अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और नीचे उतरने को तैयार नहीं है तहसीलदार शिवशंकर गुर्जर ने बताया कि सरकारी संस्थानों में इस तरह निरीक्षण की अनुमति देना प्रशासनिक नियमों के तहत उचित नहीं है मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम स्थिति संभालने में जुटी रही।

डिजिटल दुनिया में सुरक्षित कदम बढ़ाएंगी भरतपुर की बेटियां

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइबर जागरूकता कार्यक्रम, छात्राओं को बताए ऑनलाइन सुरक्षा के उपाय

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच बालिकाओं को साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरतपुर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया यह कार्यक्रम कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। महिला सशक्तिकरण केंद्र हब की जिला मिशन समन्वयक तारा कुशवाहा ने छात्राओं को साइबर

सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी सरल एवं व्यवहारिक तरीके से दी छात्राओं को बताया गया कि मोबाइल नंबर, घर का पता, स्कूल की जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी जैसी निजी सूचनाएं अनजान लोगों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेज या चैट का जवाब देने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई उन्हें समझाया गया कि साइबर अपराधी कई बार परिचित बनकर, इनाम, नौकरी या आकर्षक ऑफर का लालच देकर व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं ऐसे संदेशों की सत्यता जांच बिना उन पर भरोसा

नहीं करना चाहिए मजबूत पासवर्ड और संदिग्ध लिंक से रहे सावधान कार्यक्रम में मजबूत पासवर्ड बनाने तथा अलग-अलग डिजिटल अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखने के महत्व को समझाया गया। छात्राओं को अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी गई, क्योंकि इनके माध्यम से फर्जी वेबसाइट, साइबर ठगी या निजी जानकारी चोरी करने का प्रयास किया जा सकता है सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से करें उपयोग छात्राओं को सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो, लोकेशन और व्यक्तिगत गतिविधियों की जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने तथा अपनी प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग सुरक्षित रखने की सीख दी गई यदि किसी बालिका को ऑनलाइन धमकी, आपत्तिजनक संदेश, संदिग्ध गतिविधि या उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो उसे चुप न रहकर माता-पिता, शिक्षक अथवा संबंधित अधिकारी को तत्काल जानकारी देने की सलाह दी गई कार्यक्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर से प्रियंका राजवाड़े, महिला सशक्तिकरण केंद्र से सुश्री शैलजा गुप्ता एवं अनीता कुमारी शाह ने सक्रिय सहभागिता निभाई। विद्यालय, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया।

जिले में अब तक 827.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज, कोटाडोल में सबसे ज्यादा बारिश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में इस मानसून सीजन में लगातार बारिश का दौर जारी है। जिले में 1 जून से 21 अगस्त 2026 तक कुल 827.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है बारिश के आंकड़ों के अनुसार जिले की विभिन्न तहसीलों में वर्षा की मात्रा में अंतर देखने को मिला है सबसे अधिक वर्षा कोटाडोल तहसील में दर्ज की गई है जबकि सबसे कम बारिश खड़गवां तहसील में हुई है कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटाडोल तहसील में 964.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई जो जिले में सर्वाधिक है इसके बाद भरतपुर तहसील में 942.0 मिमी तथा मनेन्द्रगढ़ तहसील में 928.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है वहीं चिरमिरी तहसील में अब तक 855.7 मिमी बारिश हुई है आंकड़ों के मुताबिक केल्हारी तहसील में 657.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है इसके अलावा खड़गवां तहसील में 617.2 मिमी बारिश हुई है जो जिले में अब तक की सबसे कम वर्षा है इस तरह जिले में सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों के बीच करीब 347 मिमी का अंतर दर्ज किया गया है बारिश के चलते जिले के ग्रामीण और मैदानी क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना हुआ है लगातार हो रही वर्षा से नदी-नालों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है प्रशासन द्वारा वर्षा की स्थिति और जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना जताए जाने के बीच जिला प्रशासन ने नागरिकों से नदी-नालों और जलभराव वाले स्थानों से सावधानी बरतने की अपील की है तहसील स्तर पर वर्षा के आंकड़ों की निगरानी लगातार की जा रही है।

48 घंटे से बारिश नहीं, धूप से फिर बढ़ी गर्मी:मंदसौर में 4 दिन में सिर्फ 0.04 इंच ही वर्षा; 25 अगस्त तक हल्की बारिश के आसार

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर जिले में बारिश का सिलसिला थम गया है। पिछले 4 दिनों में जिले में केवल 0.04 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं, बीते 48 घंटों से शहर सहित जिले के किसी भी हिस्से में वर्षा नहीं हुई है। गुरुवार और शुक्रवार को मंदसौर में धूप खिली रही, जिसके कारण लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। दलौदा, अफजलपुर, सीतामऊ, नाहरगढ़, भानपुरा, गरोठ, सुवासरा, शामगढ़, मल्हारगढ़, पिपलियामंडी, नारायणगढ़, डिगांव और बरखेड़ा जैसे अधिकांश क्षेत्रों में भी बारिश नहीं हुई है। इन इलाकों में दिनभर धूप और उमस के कारण लोग परेशान रहे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 1 जून से 21 अगस्त तक जिले में औसतन 517.4 मिमी (20.37 इंच) बारिश दर्ज की गई है। पिछले साल इसी अवधि में 21.90 इंच बारिश हुई थी। इस प्रकार, इस साल अब तक पिछले वर्ष की तुलना में लगभग डेढ़ इंच कम बारिश हुई है।

पिछले साल से 60 मिमी कम बरसात: जिले में अब तक सबसे अधिक बारिश धुंधड़का में 645.0 मिमी दर्ज हुई है। इसके बाद भावगढ़ में 576.2 मिमी, मल्हारगढ़ में 541.0 मिमी, शामगढ़ में 538.2 मिमी, गरोठ में 527.0 मिमी, सीतामऊ में 520.0 मिमी, सुवासरा में 514.1 मिमी, मंदसौर में 501.0 मिमी, भानपुरा में 498.6 मिमी, कयामपुर में 427.5 मिमी और संजीत में 403.0 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मंदसौर तहसील में 1 जून से 21 अगस्त तक 501.0 मिमी (लगभग 19.72 इंच) बारिश दर्ज हुई है। पिछले साल इसी अवधि में तहसील में 561.0 मिमी बारिश हुई थी। इस वर्ष मंदसौर तहसील में लगभग 60 मिमी कम बारिश हुई है। पूरे जिले में पिछले साल 19 अगस्त तक कुल 6003.1 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस साल अब तक कुल 5691.6 मिमी बारिश हुई है।

25 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, जिले में अगले कुछ दिनों तक मानसून का असर बना रह सकता है। 25 अगस्त तक जिले के कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। आज और कल बारिश की गतिविधियों में अपेक्षाकृत वृद्धि हो सकती है। आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। गरज-चमक और तेज हवा के साथ मौसम में सक्रियता बढ़ सकती है।

ई-विकास 2.0 प्रणाली में किसान हित में बड़े बदलाव, अब मनचाही खाद और रिटेलर चुनने की सुविधा

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। राज्य सरकार ने किसानों को उर्वरक वितरण व्यवस्था में अधिक सरलता, पारदर्शिता और सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान) प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया है। राज्य शासन द्वारा गठित समिति से प्राप्त सुझावों को ई-विकास प्रणाली 2.0 में शामिल किया गया है। समिति का गठन कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में किसान संगठनों, निजी उर्वरक विक्रेताओं तथा अन्य संबंधित हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था।

किसान अपनी पसंद का उर्वरक खरीद सकेगा: ई-विकास 2.0 में किसान को अपनी इच्छानुसार किसी भी एक उर्वरक को खरीदने की स्वतंत्रता दी गई है। आईसीएआर की फसलवार अनुशंसा के अनुसार अथवा उससे अधिक मात्रा में किसान पहली बार में ही अपनी आवश्यकता का उर्वरक खरीद सकेगा। अतिरिक्त उर्वरक लेने के लिए 50 शब्दों में कारण लिखने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसान ड्रॉपडाउन विकल्प के माध्यम से कारण का चयन कर सकेगा। पोर्टल पर फसलवार आईसीएआर अनुशंसा के अनुसार विभिन्न उर्वरक समूहों की जानकारी भी प्रदर्शित की जा रही है। इससे किसान अपनी आवश्यकता के अनुरूप पसंदीदा उर्वरक समूह का चयन कर सकेगा।

प्रति हेक्टेयर बैग के आधार पर होगी उर्वरक की गणना: ई-विकास 2.0 में उर्वरक की गणना प्रति हेक्टेयर बैग के आधार पर की गई है। इससे किसान को अपनी भूमि और फसल के अनुसार उर्वरक की आवश्यकता समझने में आसानी होगी तथा वितरण व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित होगी।

टोकन व्यवस्था में भी किए गए महत्वपूर्ण बदलाव: मार्कफेड के डबल लॉक केन्द्रों पर प्रतिदिन 300 से अधिक टोकन जनरेट करने की आवश्यकता होने पर संख्या को जरूरत के अनुसार बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं किसान द्वारा टोकन जनरेट किए जाने के 24 घंटे बाद उसे निरस्त करने की सुविधा भी दी गई है। मार्कफेड के डबल लॉक केन्द्रों में आवश्यकता के अनुसार अधिकतम उर्वरक का भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए ऑटोमेटेड व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

फसल खराब होने पर दोबारा उर्वरक की मांग की सुविधा: यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है और उसे पुनः उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो ई-विकास प्रणाली की एक्सेप्शनल हैंडलिंग व्यवस्था के माध्यम से उर्वरक की मांग करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों का अनुमोदन संबंधित तहसीलदार अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा 48 घंटे के भीतर किया जाएगा।

जल्द व्हाट्सएप से मिलेगा टोकन: ई-विकास 2.0 के तहत किसानों को मोबाइल पर WhatsApp Bot के माध्यम से टोकन जनरेट करने की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। किसान व्हाट्सएप पर HELP/मदद लिखकर टोकन, रिटेलर, उर्वरक, उठाव की तिथि तथा टोकन की वैधता सहित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेगा और इसके आधार पर उर्वरक खरीद सकेगा। राज्य सरकार के अनुसार यह पहल मध्यप्रदेश में तकनीक आधारित और किसान हितैषी डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसे देश में पहली बार लागू की जा रही ऐसी व्यवस्था के रूप में बताया गया है।

किसान आईडी, पैक्स सदस्यता और अग्रिम उर्वरक उठाव का: प्रदेश में सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी बनाने, अग्रिम उर्वरक उठाव तथा पैक्स सदस्यता के लिए विशेष अभियान 20 अगस्त 2026 से चलाया जाएगा। किसानों से अभियान का लाभ उठाकर आवश्यक पंजीयन एवं सदस्यता प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई है। राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से आईएफएमएस पोर्टल एवं ई-विकास पोर्टल के एकीकरण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही दो अलग-अलग विक्रय केन्द्रों के PoS से उर्वरक लेने के बीच लागू 60 मिनट की बाध्यता को समाप्त करने का भी अनुरोध किया गया है। ई-विकास 2.0 में भविष्य में किसान हित में उपलब्ध होने वाली नई सुविधाओं तथा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों की जानकारी ई-विकास पोर्टल और विभिन्न डिजिटल माध्यमों से किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार: किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अनुसार प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। 1 अप्रैल 2026 से अब तक यूरिया की कुल उपलब्धता 17.57 लाख मीट्रिक टन रही है, जिसमें से किसानों द्वारा 13.18 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उठाव किया गया। वर्तमान में प्रदेश में 4.39 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यूरिया की उपलब्धता 1.80 लाख मीट्रिक टन थी। इसी अवधि में डीएपी एवं एनपीके की कुल उपलब्धता 11.43 लाख मीट्रिक टन रही, जिसमें से किसानों द्वारा 7.23 लाख मीट्रिक टन का उठाव किया गया। वर्तमान में 4.20 लाख मीट्रिक टन डीएपी एवं एनपीके उपलब्ध है। पिछले वर्ष इसी अवधि में इन दोनों उर्वरकों की उपलब्धता 3.19 लाख मीट्रिक टन थी।

रतलाम में फास्ट फूड कारोबारी से 20 लाख की ठगी डायमंड बिजनेस में निवेश के नाम पर ऑनलाइन ट्रांसफर कराए रुपए, एफडी तक तुड़वाई

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम में फास्ट फूड व्यवसायी के साथ बिजनेस में रुपए लगाकर डबल करने के लालच में 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। यूपी के व्यक्ति में बातों में लेकर रुपए तो ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए, लेकिन रुपए नहीं लौटाए। शिकायत के बाद पुलिस ने गुरुवार शाम धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायी महेंद्रसिंह (30) ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि एक दोस्त के जरिए मेरी मुलाकात रवींद्रसिंह टांक (33) निवासी बिजनौर (उत्तरप्रदेश) हाल मुकाम इंदौर से हुई थी। 12 फरवरी 2025 को रवींद्रसिंह साथी हरजिंदरसिंह के साथ मेरे घर आया था। रवींद्रसिंह ने

मुझे बताया कि मेरा डायमंड का व्यवसाय है। उसने मुझे लालच दिया कि इस बिजनेस में यदि रुपए लगाएंगे तो डबल रकम मिलेगी।

ऑनलाइन ट्रांसफर किए रुपए: रवींद्र की बात में आकर महेंद्रसिंह ने 13 फरवरी 2025 को अपनी मां के मोबाइल से रवींद्रसिंह के मोबाइल पर 30 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके बाद बड़े भाई के साथ ही भाभी, एयरटेल पैमेंट बैंक के जरिए भी उसको ऑनलाइन पैमेंट किया। इस तरह कुल उसके खाते में 7 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। शुरू में तीन लाख रुपए वापस कर उसने विश्वास में ले लिया। इसके बाद 13 फरवरी 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 तक महेंद्रसिंह ने अपने और परिजनों के खाते से करीब 20 लाख रुपए उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए।

एफडी तोड़ दिए रुपए

फिर जब ज्यादा अमाउंट हो गया तो रुपए देना बंद कर दिए। कहने लगा मेरे कारोबार में घाटा हो गया है। अब कुछ दिन बाद व्यवस्था कर रकम लौटा दूंगा। पिछले जून से अब तक तक वह केवल आश्वासन ही दे रहा है। महेंद्रसिंह के अनुसार उसके पापा के रिटायर्ड होने पर जो रुपए मिले थे वो और अपनी एफडी तोड़कर रवींद्रसिंह को रुपए दिए थे। रवींद्रसिंह निवासी इंदौर ने डायमंड के व्यापार में इंवेस्टमेंट कर दोगुने रुपए देने के नाम पर मेरे साथ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने बताया धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामला जांच में लिया है।

इटारसी से दो एक्सप्रेस ट्रेनें नियमित चलेंगी:अक्टूबर से यात्रियों को मिलेगी पूर्वोत्तर और दक्षिण की कनेक्टिविटी

मीडिया ऑडीटर, इटारसी (निप्र)। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इनमें रानी कमलापति-अगरतला साप्ताहिक एक्सप्रेस और जबलपुर-कोयंबटूर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं। ये दोनों ट्रेनें इटारसी होकर गुजरेंगी, जिससे नर्मदापुरम जिले और आसपास के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ट्रेन संख्या 11665/11666 रानी कमलापति-अगरतला-रानी कमलापति साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन 22 अक्टूबर से रानी कमलापति से और 25 अक्टूबर से अगरतला से शुरू होगा। रानी कमलापति से यह ट्रेन प्रत्येक

गुरुवार को और अगरतला से प्रत्येक रविवार को रवाना होगी। इस ट्रेन का ठहराव नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, दानापुर, पाटलिपुत्र, कटिहार, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इसमें कुल 22 कोच होंगे। इसी तरह, ट्रेन संख्या 20160/20159 जबलपुर-कोयंबटूर-जबलपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नियमित संचालन 23 अक्टूबर से जबलपुर से और 26 अक्टूबर से कोयंबटूर से शुरू होगा। जबलपुर से यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को और कोयंबटूर से प्रत्येक सोमवार को चलेगी।

यहां लेंगी स्टाप: यह ट्रेन नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, पनवेल, रत्नागिरी, मडगांव, कन्नूर, कोझिकोड, पालक्काड जैसे स्टेशनों से होकर कोयंबटूर पहुंचेगी। इसमें 24 कोच होंगे, जिनमें फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल हैं। इन दोनों ट्रेनों के नियमित होने से इटारसी से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

रायसेन में नशे में सड़क पर लेटी युवती:देर रात हंगामा किया, मोबाइल गुम होने से परेशान थी; पुलिस ने ढूंढकर लौटाया

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन शहर के महामाया चौक पर गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात एक युवती ने नशे की हालत में हंगामा किया। देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है। युवती सड़क पर लेटकर लोगों और पुलिस से अभद्रता करती दिखी। सामने आए वीडियो में युवती कभी सड़क पर बैठी तो कभी लेटी हुई नजर आ रही है। वह नशे की हालत में इतनी बेसुध थी कि सड़क पर गिरने के बाद खुद उठ भी नहीं पा रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे उठाकर सड़क किनारे किया। पुलिस के पहुंचने पर भी युवती का हंगामा जारी रहा।

- परेशान होकर हंगामा कर रही थी

कोतवाली थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल ने बताया कि युवती का मोबाइल कहीं गिर गया था, जिसके कारण वह परेशान होकर हंगामा कर रही थी। पुलिस ने युवती का गुम हुआ मोबाइल ढूंढकर उसे वापस कर दिया।

महिंद्रा ओजा भारतीय बागवानी के भविष्य को दे रहा नई दिशा

मीडिया ऑडीटर, जबलपुर (निप्र)। महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने ओजा प्लेटफॉर्म के तीन वर्ष पूरे होने पर इसकी उपलब्धियों को रेखांकित किया कंपनी के अनुसार ओजा प्लेटफॉर्म ने भारत में बागवानी, अंगूर के बाग, फलों के बागान, अंतर-फसल खेती, गन्ने और अन्य विशेष कृषि अनुप्रयोगों के लिए कॉम्पैक्ट एवं हल्के 4WD ट्रैक्टरों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। मजबूत तकनीक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित ओजा रेंज अब 21 से 30 एचपी श्रेणी में कई उत्पादों तक विस्तारित हो चुकी है। कंपनी के अनुसार यह भारत में तेजी से बढ़ते ट्रैक्टर सेगमेंट में शामिल है ओजा ट्रैक्टरों को विशेष रूप से

उच्च-मूल्य वाली फसलों और विशिष्ट खेती की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ओजा रेंज में 4WD को मानक सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इसका कॉम्पैक्ट आकार, बेहतर गतिशीलता और पावर-टू-वेट अनुपात इसे सीमित जगहों और अलग-अलग कृषि परिस्थितियों में उपयोगी बनाता है नैरो-ट्रैक कॉन्फिगरेशन के कारण किसान बागानों और कतार वाली फसलों के बीच आसानी से ट्रैक्टर का संचालन कर सकते हैं। साथ ही, विभिन्न कृषि उपकरणों के साथ इसकी अनुकूलता खेती के अलग-अलग कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाती है।

नौकरीपेशा और छात्रों के लिए संडे स्पेशल:सीहोर में 2 घंटे की योग क्लास, सुबह 7 बजे से होगा प्राणायाम और योगाभ्यास

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर के शहरवासियों को योग और स्वस्थ जीवनशैली से जोड़ने के लिए रविवार को निःशुल्क मेगा योग शिविर लगाया जाएगा। शिविर का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा।

योगाचार्य सिखाएंगे आसान तरीके: आयोजन समिति के सदस्य कपिल सूर्यवंशी ने बताया कि दो घंटे के इस विशेष शिविर में प्रसिद्ध योगाचार्य दिनेश शर्मा लोगों को स्वस्थ और निरोग रहने के आसान तरीके बताएंगे। इस दौरान प्राणायाम के साथ कई जरूरी योगासन करने का तरीका भी सिखाया जाएगा।

रोज होती हैं योग की कक्षाएं: पुलिस परेड ग्राउंड में रोज सुबह योग की नियमित कक्षाएं भी चलती हैं। योगाचार्य दिनेश शर्मा यहां लोगों को योगाभ्यास कराते हैं। मेगा शिविर का मकसद इन कक्षाओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों को

जोड़ना है। आयोजकों ने बताया कि नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और छात्रों को ध्यान में रखते हुए रविवार को शिविर रखा गया है, ताकि वे छुट्टी के दिन इसमें आसानी से शामिल हो सकें।

योगा मैट साथ लाना जरूरी: आयोजकों ने शहरवासियों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिविर में पहुंचने की अपील की है। महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। शिविर में आने वाले लोगों को अपने साथ योगा मैट लाना जरूरी होगा। आयोजकों ने लोगों से अपील की है। कि रविवार सुबह समय निकालकर पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे और योगाचार्य दिनेश शर्मा के मार्गदर्शन में योग सीखकर खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाएं।

मिठाई पर महंगाई की मार:सीहोर में रक्षाबंधन से पहले चीनी-बादाम के दाम बढ़े, जेब पर पड़ेगा असर

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। रक्षाबंधन से पहले बाजार में मिठास पर महंगाई का असर दिखाई देने लगा है। सीहोर में बीते एक महीने के दौरान चीनी और बादाम के दामों में तेज बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर रक्षाबंधन पर घरों में बनने वाली मिठाइयों के साथ-साथ बाजार में बिकने वाली तैयार मिठाइयों की कीमतों पर पड़ने की संभावना है।

चीनी 20 रुपये और बादाम 200 रुपये महंगा: बीते एक महीने में चीनी के दाम में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। चीनी अब करीब 70 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। वहीं, बादाम की कीमत में 200 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया

है और इसकी कीमत बढ़कर 1000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। गुड़ के दाम भी 15 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर करीब 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं।

त्योहार में बढ़ जाती है मांग: रक्षाबंधन के त्योहार पर घरों में मावे की गुजिया, लड्डू और गुलाब जामुन सहित कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा बाजार में फेणी और अन्य पारंपरिक मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है। इन मिठाइयों में चीनी और बादाम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे त्योहार के बजट पर पड़ सकता है।

मिठाई की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका: स्थानीय दुकानदार महेश गुजराती के अनुसार, पिछले एक महीने में चीनी और बादाम दोनों के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

छतरपुर में एक दिन में सर्पदंश से 4 मौतें:डॉक्टरों की अपील- झाड़-फूंक में न गंवाएं समय

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर में सांप के डसने से एक ही दिन में चार लोगों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में गुरुवार को इन सभी मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया। मृतकों में कृतिक, रक्षा, रचना और राकेश शामिल हैं। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिला अस्पताल के डॉक्टर रवि सोनी ने पुष्टि की कि गुरुवार को हुए सभी चार पोस्टमार्टम सर्पदंश के मामलों से संबंधित थे। इससे पहले, सिविल सर्जन डॉ. शरद चौरसिया ने बताया था कि पिछले दो दिनों में भी सर्पदंश के 14 मरीज इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। इनमें से एक मरीज को रेफर किया गया था, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अपील- झाड़-फूंक में समय बर्बाद न करें डॉक्टरों ने सर्पदंश के मामलों में देरी से इलाज को एक बड़ी समस्या बताया है। डॉ. रवि सोनी के अनुसार, सांप के काटने के बाद कई लोग अस्पताल जाने के बजाय झाड़-फूंक या स्थानीय उपचार पर निर्भर रहते हैं।

खंडवा में शक्कर 45 से बढ़कर 65 किलो चाय भी हुई महंगी, त्योहार बाद मिठाई के दाम 80 तक बढ़ने के आसार

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा में महंगाई का असर अब आम आदमी की जेब पर सीधे दिखाई देने लगा है। खंडवा के बाजार में रोजमर्रा की जरूरत वाली शक्कर के दाम करीब ?20 प्रति किलो बढ़ गए हैं। कुछ समय पहले तक 45 रुपए किलो बिकने वाली शक्कर अब 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है। शक्कर महंगी होने का असर चाय और मिठाई कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है।

चाय के दाम भी बढ़े: शक्कर के दाम बढ़ने के बाद चाय कारोबारियों की लागत बढ़ गई है। पहले करीब 7 रुपए में मिलने वाली एक कप चाय अब 10 रुपए तक पहुंच गई है। दुकानदारों का कहना है कि शक्कर के अलावा अन्य सामग्री के दाम बढ़ने से पुराने रेट पर चाय बेचना मुश्किल हो रहा है।

त्योहार पर मिठाई के दाम फिलहाल स्थिरःत रक्षाबंधन सहित आने वाले त्योहारों को देखते हुए मिठाई कारोबारियों ने फिलहाल दाम बढ़ाने से राहत दी है। खंडवा में कई तरह की मिठाइयां अभी करीब 480 रुपए किलो बिक रही हैं। कारोबारियों के मुताबिक, पुराना शक्कर स्टॉक होने के कारण त्योहार के दौरान मिठाई के दाम तत्काल नहीं बढ़ाए जाएंगे। हालांकि, पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद नए स्टॉक के साथ मिठाई की कीमत में करीब ?80 प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में 480 रुपए किलो वाली मिठाई करीब 560 रुपए किलो तक पहुंच सकती है।

मिठाई कारोबारियों की बढ़ी लागत: मिठाई बनाने में शक्कर के साथ दूध, मावा, घी, ड्रायफ्रूट और अन्य सामग्री का इस्तेमाल होता है। शक्कर के दाम बढ़ने से मिठाई की कुल लागत पर सीधा असर पड़ा है। कारोबारियों का कहना है कि त्योहार के समय मांग बढ़ने के बावजूद ग्राहकों पर अचानक बढ़ी लागत का पूरा बोझ डालना मुश्किल है। इसलिए फिलहाल पुराने स्टॉक से काम चलाया जा रहा है। नया स्टॉक आने के बाद कीमतों में बदलाव की संभावना है।

महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन: इधर, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस शुक्रवार को खंडवा में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शाम 4 बजे गांधी भवन में एकत्र होंगे। इसके बाद रैली के रूप में केवलराम चौराहा पहुंचकर महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शक्कर जैसी जरूरी वस्तु के दाम बढ़ने का सीधा असर आम परिवार के बजट पर पड़ रहा है।

आम आदमी के बजट पर असर: शक्कर महंगी होने का असर सिर्फ घर की रसोई तक सीमित नहीं है। चाय, मिठाई और शक्कर से तैयार होने वाले कई खाद्य पदार्थों की लागत भी बढ़ रही है। यदि शक्कर के बढ़े हुए दाम लंबे समय तक बने रहे, ।

कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने टीम इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी की

कोलंबो,एजेसीं। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंडिया हाउस में भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी की। भारतीय उच्चायुक्त झा ने गुरुवार रात भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ही श्रीलंकाई टीम की भी मेजबानी की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी दी है और इसे एक 'यादगार शाम' बताया है। बीसीसीआई ने अपने एक्स में लिखा, 'कोलंबो में एक यादगार शाम। श्रीलंका में इंडिया के उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले कोलंबो के इंडिया हाउस में भारतीय टीम की मेजबानी की।' झा ने दोनों टीमों की मेजबानी करके खुशी जाहिर की और कार्यक्रम की कुछ झलकियां एक्स पर साझा की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'टीम इंडिया के साथ चीयर कर रहा हूं। श्रीलंका में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचों के दौरान भारतीय और श्रीलंकाई पुरुष क्रिकेट टीमों की मेजबानी करके खुशी हो रही है। खेल के लिए एक जैसे जुनून से बंधा, क्रिकेट भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा रहने वाले रिश्तों को और मजबूत कर रहा है।'

सिनसिनाटी ओपन

आर्थर फिल्स ने थियागो अगस्टिन टिरेंटे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

सिनसिनाटी ,एजेसीं। आर्थर फिल्स ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फिल्स ने 64 मिनट तक चले मुकाबले में थियागो अगस्टिन टिरेंटे को 6-3, 6-2 से हराया। फिल्स ने इस सीजन के तीसरे एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 22 साल के फिल्स एक सीजन में तीन मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी बन गए। उनसे पहले गाइ फॉरगेट ने 1991 में यह उपलब्धि हासिल की थी। फरवरी में आठ महीने की चोट के बाद वापसी करते हुए फिल्स का शानदार सीजन रहा है। एटीपी जीत/हार इंडेक्स के मुताबिक, इस साल फ्रेंचमैन का टूर-लेवल रिकॉर्ड 30-10 रहा है, जिसमें बार्सिलोना में एक खिताब और मियामी और मैड्रिड में मास्टर्स 1000 इवेंट्स के सेमीफाइनल में पहुंचना शामिल है। पहले सेट में 4-3 पर एक अहम ब्रेक हासिल करने के बाद, फिल्स ने लगातार जबरदस्त फोरहैंड लगाए, जिससे टिरांटे लगातार बैकफुट पर रहे। एटीपी के मुताबिक, 22 साल के खिलाड़ी ने दूसरे सेट में अर्जेंटीना के खिलाड़ी की सर्विस दो बार तोड़ी और पूरे मैच के दौरान उन्हें कभी भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। अब वह टाइटल मैच में जगह बनाने के लिए फ्लेवियो कोबोली से भिड़ेंगे, दोनों खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंचना चाहते हैं। कोबोली ने घरेलू पसंदीदा टॉमी पॉल के खिलाफ 2-6, 6-3, 6-4 से जीत हासिल की और ओहियो में अपने पहले मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंच गए। 24 साल के खिलाड़ी अब जून में रोलैंड गैरोस चैंपियनशिप मैच में पहुंचने के बाद अपने पहले सेमीफाइनल की तैयारी करेंगे। वह 2024 और 2025 में जैनिक सिनर के बाद सिनसिनाटी में अंतिम चार में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे इटैलियन खिलाड़ी हैं। पॉल के खिलाफ जीत के साथ, कोबोली ने यह भी पक्का कर लिया कि वह सोमवार को एटीपी रैंकिंग में अपने करियर की नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वह अभी लाइव रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 6 पर हैं।

इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंची, एलेना रयबाकिना इंजरी की वजह से बाहर

सिनसिनाटी ,एजेसीं। एलेना रयबाकिना को सिनसिनाटी ओपन क्वार्टर फाइनल मैच से बाएं टखने में चोट के कारण बाहर होना पड़ा। इंजरी की वजह से जहां वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं, वहीं उनकी विपक्षी इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंच गईं। मैच के दौरान स्वियाटेक 4-1 से आगे थीं और रयबाकिना 40-15 पर सर्व कर रही थीं। उसी समय रयबाकिना के लिए मुश्किल शुरू हुई। रयबाकिना नेट पर एक रैली खत्म नहीं कर सकीं। डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के अनुसार, अगले पॉइंट पर उन्हें अपनी पहली सर्व पर पुश करने में मुश्किल हुई, जो सिर्फ तीन शॉट तक चली, और गेम के बीच में मेडिकल जांच के बाद, रयबाकिना ने कुछ देर बाद मैच खत्म करने का फैसला किया। रायबाकिना ने कहा, 'मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सर्व से पुश भी नहीं कर पा रही थी। चलने में दर्द हो रहा है। एमआरआई के बाद समस्या के बारे में और पता चलेगा।' उन्होंने कहा, 'यह मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। कनाडा में बहुत सारे मैच खेलने और यहां लगातार दो मैच खेलने के बाद और मैच से पहले ठीक लग रहा था लेकिन बदकिस्मती से एक गलत मूवमेंट, एक लैंडिंग, और समस्या शुरू हो गई।' बुधवार को चौथे राउंड में सारा बेजलेक से सबालेंका के हारने के बाद, रायबाकिना को वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग लेने के लिए सिनसिनाटी में फाइनल में पहुंचना था। इसके बजाय, सबालेंका अगले हफ्ते यूएस ओपन में टॉप स्पॉट बनाए रखेंगी। टोरंटो चैंपियन स्वियाटेक का मुकाबला सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला से होगा। स्वियाटेक ने कहा, 'मुझे पता है कि यह भी जरूरी है। लेकिन यूएस ओपन तो यूएस ओपन है। मुझे उम्मीद है कि वह इसके लिए तैयार होगी। वह दुनिया में नंबर 1 बनने के बहुत करीब है। मुझे लगा कि हम अच्छा मैच खेल रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य प्राथमिकता है। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगी।'

त्रिसा-गायत्री ने दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी को हराया

महिला डबल्स में मेडल पक्का

नई दिल्ली ,एजेसीं। भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी जी यिफान और झांग शुक्सियन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। त्रिसा-गायत्री की जीत ने देश के लिए मेडल पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने एक गेम पीछे रहने के बाद चीनी जोड़ी पर 16-21, 21-15, 21-13 से जीत दर्ज की और महिला डबल्स में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली दूसरी जोड़ी बन गई। इससे पहले महिला डबल्स में 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने कांस्य पदक जीता था। शुरुआत में भारतीय जोड़ी कमजोर दिखी क्योंकि जिया और झांग ने 6-2 की बढ़त बना ली और शुरुआती गेम तक अपनी बढ़त बनाए रखी। त्रिसा और गायत्री ने धीरे-धीरे अपनी आक्रामक रिदम पाई, अपने पावरफुल स्मैश और नेट के दम पर अंतर को 8-9 कर दिया। हालांकि, रिकवरी इतनी नहीं थी कि चीनी खिलाड़ी को 11-8 की बढ़त के साथ ब्रेक में जाने से रोका जा सके और आखिरकार शुरुआती गेम 21-16 से जीत लिया।दूसरे गेम भारतीयों ने अपने विरोधियों को वैसा नियंत्रण नहीं करने दिया, लंबी रैलियों में उनका मुकाबला किया और दबाव में डिफेंड करते हुए इंटरवल पर 11-10 की मामूली बढ़त हासिल की। वहां से, त्रिसा और गायत्री और ज्यादा आक्रामक हो गईं। उनके क्रॉस-कोर्ट अटैक ने बार-बार चीनी जोड़ी को कोर्ट के पार खींचा, जबकि उनके डिफेंस ने जिया और झांग के दबाव को झेला। इंडियन्स ने 17-14 की बढ़त के साथ शुरुआत की और फिर गेम 21-15 से खत्म करके निर्णायक बना दिया। निर्णायक गेम में 4-4 से बराबरी की शुरुआत के बाद, त्रिसा ने एक जोरदार स्मैश से ब्रेकथ्रू पाया, और भारतीय जोड़ी ने बढ़त बना ली। लगातार सात पॉइंट्स ने मैच का पासा पलट दिया, जिससे वे 4-4 से 9-4 पर आ गए। त्रिसा के अटैक ने चीनी जोड़ी को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। भारतीय जोड़ी ने 11-5 की बड़ी बढ़त के साथ इंटरवल में एंट्री की। साइड बदलने के बाद, जिया और झांग ने थोड़ी देर के लिए अपनी चुनौती को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने लगातार तीन पॉइंट्स जीतकर अपनी लय वापस पा ली। चीनी जोड़ी पर बढ़ते दबाव के साथ, उनके गेम में गलतियां होने लगीं। 18-9 पर, भारतीय बस बराबरी पर थे। झांग के शॉट को आउट दिए जाने के बाद एक समीक्षा से नतीजे में ज्यादा बदलाव नहीं आया। चीनी जोड़ी की दो और गलतियों ने त्रिसा और गायत्री को निर्णायक पाइंट दिला दिए।

रोमांचक मुकाबले में वांग से मिली सिंधु को हार

वर्ल्ड चैंपियनशिप का सफर समाप्त

नई दिल्ली,एजेसीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुरुवार को हार के साथ पीवी सिंधु का 'विमेंस सिंगल्स' में सफर समाप्त हो गया। इसी के साथ सिंधु चैंपियनशिप में रिकॉर्ड छठा मेडल जीतने से चूक गईं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक 'राउंड-ऑफ-16' मुकाबले में चीन की वांग झी यी ने उन्हें 21-11, 15-21, 21-17 से मात दी। इस हार के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु का शानदार सिलसिला भी टूट गया। इससे पहले, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंधु ने चीनी खिलाड़ियों को आठ बार हराया था, लेकिन वांग इस मंच पर उन्हें हराने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। पहले गेम में दोनों खिलाड़ी आसान गलतियों से बचने की कोशिश कर रही थीं और एक-दूसरे को लंबे और धैर्यपूर्ण एक्सचेंज के लिए मजबूर कर रहे थे। वांग को सिंधु को फ्रंट कोर्ट पर दौड़ाने में सफलता मिली, जबकि भारतीय खिलाड़ी ने बार-बार अपनी प्रतिद्वंद्वी को अटैक करने का स्पष्ट मौका नहीं दिया। वांग इंटरवल तक 11-8 से आगे थीं। इसके बाद मुकाबला तेजी से उनके पक्ष में झुक गया, क्योंकि सिंधु ने बिना दबाव के गलतियों और गलत अंदाजे के कारण प्वाइंट गंवाने शुरू कर दिए।

वांग ने इसका पूरा फायदा उठाया और अपने सटीक ड्रॉप्स और अटैकिंग स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए गेम 21-11 से जीत लिया। घरेलू दर्शकों की उम्मीदों को देखते हुए सिंधु ने दूसरे गेम में अपनी रणनीति बदलकर अधिक धैर्य के साथ शुरुआत की और तुरंत चार प्वाइंट्स की बढ़त बना ली, जबकि वांग उसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। चीनी खिलाड़ी ने सिंधु को लंबी रैलियों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने बेहतरीन ड्रिबल और ड्रॉप्स से इसका जवाब दिया। वांग के 15-15 से बराबरी करने के बाद भी सिंधु ने अपनी लय वापस हासिल की। उन्होंने लगातार छह प्वाइंट्स हासिल किए और मैच को निर्णायक गेम तक ले गईं। तीसरे गेम की शुरुआत में सिंधु फिर से नियंत्रण में दिखीं। वह 3-0 से आगे हुईं और इसके बाद 8-4 की बढ़त बना ली। हालांकि, वांग ने मैच को हाथ से नहीं जाने दिया। सिंधु की लगातार तीन गलतियों ने चीनी खिलाड़ी को आगे बढ़ने में मदद की, हालांकि इंटरवल तक भारतीय खिलाड़ी 11-10 से आगे थीं। आखिरी दौर में मुकाबले का सबसे रोमांचक पल देखने को मिला। 16-16 के स्कोर पर वांग बुरी तरह गिर गईं और उन्हें मेडिकल टाइम-आउट लेना पड़ा। खेल दोबारा शुरू होने पर सिंधु अपना संयम नहीं बनाए रख सकीं और लगातार चार गलतियां कर बैठीं, जिससे वांग को मैच प्वाइंट मिल गया।

नीरज चोपड़ा को श्रीलंका के रुमेश पाथिरगे से फिर मिलेगी चुनौती

नई दिल्ली । ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने के बाद, दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा शुक्रवार को लॉजेन डायमंड लीग में एक बार फिर से अपना दमदार प्रदर्शन दिखाने को तैयार हैं। लॉजेन डायमंड लीग बेहद रोमांचक होगी। इस इवेंट में कई ओलंपिक, वर्ल्ड और यूरोपियन चैंपियन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पुरुषों की जैवलिन स्पर्धा में दक्षिण एशिया के दो सबसे बड़े स्टार भारत के नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रुमेश थरंगा पाथिरगे, एक बार फिर आमने-सामने होंगे। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के स्टेड ओलंपिक डे ला पोंटेस में होने वाली लॉजेन डायमंड लीग 2026 में टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लॉजेन में चोपड़ा चौथी बार उतरेंगे। यह लीग चोपड़ा का 2026 एथलेटिक्स सीजन का तीसरा प्रतियोगी इवेंट है।

श्रीलंका के पाथिरगे ने जून में रोम में 92.62 मीटर के साथ ब्रुसेल्स में होने वाले फाइनल में अपनी जगह बुक कर ली है। वहीं, पूर्व ओलंपिक और डायमंड लीग चैंपियन चोपड़ा स्टैंडिंग में पीछे हैं। उन्हें लॉजेन में एक बड़े करिश्माई थ्रो की जरूरत है।

नीरज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जैसे ही एक मजबूत फील्ड में यूरोपियन स्टार्स के साथ मुकाबला करेंगे। पिछले चार ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पांच जेवलिन सुपरस्टार्स 21 अगस्त को एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे।

इवेंट में नीरज चोपड़ा और पाथिरगे के अलावा त्रिनिदाद एंड टोबैगो के वालकॉट और ग्रेनाडा के पीटर्स हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया था।

मैच भारतीय समयानुसार शुक्रवार रात 11:52 से शुरू होगा।

लॉजेन डायमंड लीग 2026 की भारत में डायमंड लीग की आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगी।

भारतीय दर्शक स्पोर्ट्स18 पर लॉजेन डायमंड लीग देख सकते हैं, जबकि जियोसिनेमा पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है।

भारतीय फुटबॉल का बड़ा नाम, 1960 ओलंपिक में किया था देश का प्रतिनिधित्व

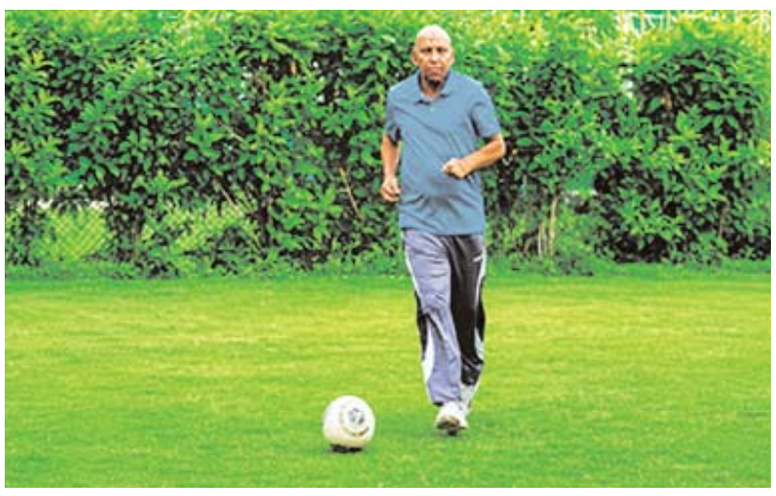

नई दिल्ली ,एजेसीं। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन भारत में इस खेल को अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर वाली प्रसिद्धी नहीं मिली है। सरकारी उपेक्षा का शिकार फुटबॉल देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। फुटबॉल की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा खराब हुई है, लेकिन पहले भी इस खेल की स्थिति आदर्श नहीं थी। इसके बावजूद सैयद शाहिद हाकिम जैसे खिलाड़ियों ने इस खेल को जिंदा रखा है। सैयद शाहिद हाकिम का नाम उन खिलाड़ियों में लिया जाता है, जिन्होंने अपने दौर में भारतीय फुटबॉल को जिंदा रखने में अपनी पूरी ऊर्जा एक खिलाड़ी और प्रशिक्षक के तौर पर लगाई। सैयद शाहिद हाकिम का जन्म 23 जून, 1939 को हैदराबाद में हुआ। शाहिद को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा अपने पिता सैयद अब्दुल रहीम से मिली।

अब्दुल रहीम भी अपने दौर के बेहतरीन फुटबॉलर रहे थे और फॉरवर्ड के तौर पर खेलते थे। शाहिद ने अपने पिता से ही फुटबॉल की बारीकियां सीखीं और इस खेल में करियर बनाने का निर्णय लिया। शाहिद 1960 में रोम ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। उस समय उनके पिता ही भारतीय टीम के कोच थे। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और वह ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सकी। फिर भी भारत ने फ्रांस के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलकर अपनी छाप छोड़ी थी। राष्ट्रीय टीम के अलावा शाहिद घरेलू फुटबॉल में सर्विसेज की तरफ से खेले। सर्विसेज की ओर से खेलते हुए उन्होंने प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी जीती थी। भारतीय वायु सेना की टीम का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। बतौर खिलाड़ी संन्यास लेने के बाद इंटरनेशनल रेफरी भी बने। उन्होंने 1988 में एएफसी एशियन कप में अंपायरिंग की। हालांकि, सैयद शाहिद हाकिम को एक खिलाड़ी से ज्यादा फुटबॉल कोच के रूप में सफलता मिली। वह भारतीय टीम के सहायक कोच रहे थे। बतौर कोच उन्होंने भारतीय फुटबॉल को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए। घरेलू फुटबॉल में वह महिंद्रा यूनाइटेड, सालगांवकर और बंगाल मुंबई के कोच रहे। भारतीय फुटबॉल में एक खिलाड़ी और प्रशिक्षक के तौर सैयद शाहिद हाकिम के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2017 में खेल क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया था। वह द्रोणाचार्य लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। 82 वर्ष की अवस्था में सैयद शाहिद हाकिम का निधन 22 अगस्त, 2021 को कलबुर्गी, कर्नाटक में हुआ था।

प्राइज मनी में भारी वृद्धि, एकल विजेता को मिलेगी इतनी बड़ी राशि

नई दिल्ली ,एजेसीं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खिलाड़ियों द्वारा प्राइज मनी बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। यूएस ओपन 2026 में खिलाड़ियों की ये मांग पूरी होने वाली है। यूएस ओपन में इस बार खिलाड़ियों के प्राइज मनी में इजाफा होने वाला है। यूएस ओपन की प्राइज मनी में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। खिलाड़ियों की कुल सैलरी बढ़कर 108 मिलियन डॉलर हो गई है। टूर्नामेंट से पहले, यूएसटीए (यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन) ने एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की। यूएसटीए के सीईओ क्रेग टिली ने कहा कि यह कदम खेल के आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो सकता है। यह एथलीटों में कई सालों के निवेश में एक अहम पहला कदम है क्योंकि यूएस ओपन खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा आर्थिक मौका और खिलाड़ियों, फैंस और पार्टनर्स के लिए टेनिस में सबसे कीमती प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एकल विजेता को 52.65 करोड़ मिलेंगे। वहीं, एकल फाइनल में हारने वाले खिलाड़ी को करीब 26.80 करोड़ रुपये (2.8 मिलियन) दिए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को लगभग 7.46 करोड़ रुपये (780,000) और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले प्लेयर्स को करीब 13.88 करोड़ रुपये (1.45 मिलियन) मिलेंगे। डबल्स मुकाबलों में पुरुष, महिला और मिक्स जीतने वाले प्लेयर्स को लगभग 9.57 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिन्हें वे आपस में बाटेंगी। वहीं उपविजेता टीमों को करीब 5,00,000 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। इसके अलावा, व्हीलचेयर सिंगल्स के चैंपियन्स को लगभग 99 लाख रुपये (1,04,000) की इनामी राशि मिलेगी। पहले ही मैच में हारकर बाहर होने वाले खिलाड़ी को भी लगभग भारतीय रुपये में 1.34 करोड़ रुपये (140,000) मिलेंगे। यूएस ओपन रोमांचक होने वाला है। पिछले 4 महीने से पेशेवर टेनिस से दूर रहे पूर्व चैंपियन कार्लोस अल्काराज अपना खिताब बचाने के लिए उतरेंगे। अल्काराज ने अप्रैल के बाद से एक भी मैच नहीं खेला है। उन्हें बार्सिलोना ओपन के दौरान कलाई में चोट लग गई थी। चोट की वजह से वह फ्रेंच ओपन, विंबलडन और कई दूसरे टूर्नामेंट से भी बाहर रहे। यूएस ओपन 2026 की शुरुआत 23 अगस्त से होगी और 13 सितंबर को पुरुषों के फाइनल के साथ खत्म होगा।

जैकब मार्टिन को 22 साल पुराने में पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया

नई दिल्ली ,एजेसीं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में बड़ी राहत दी है। 2004 के इस मामले में कोर्ट ने मार्टिन को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर पर फर्जी यूके आव्रजन स्टाम्प, यात्रा व्यवस्था और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा आरोप लगाया गया था, जिसे साबित नहीं किया जा सका। अदालत को वित्तीय लेनदेन या अजवा स्पोर्ट्स क्लब पर उनके स्वामित्व या नियंत्रण से जुड़ा कोई भी ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं मिला। कई गवाह भी इन आरोपों को साबित करने में विफल रहे। मीडिया से बात करते हुए मार्टिन ने बताया कि यह मामला 2004 में उनकी टीम के एक सदस्य द्वारा ब्रिटेन का वीजा समाप्त होने के बाद वहां रुकने और फर्जी आव्रजन स्टाम्प लगवाकर भारत लौटने के बाद शुरू हुआ था। मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था। बाद में उनका नाम मामले में जोड़ दिया गया। घटना के बारे में मार्टिन ने कहा, 2004 में टीम इंग्लैंड खेलने गई थी। जो टीम 2004 में इंग्लैंड गई थी, उसमें से एक लड़के को छोड़कर बाकी सब वापस आ गए। वीजा की वैधता छह महीने की थी, वह छह महीने तक रह सकता था। वह इससे अधिक समय तक रुका रहा। किसी के जरिए उसने वहां फर्जी स्टैंपिंग करवा ली। फर्जी स्टैंपिंग कराने के बाद जब वह भारत वापस आया, तो उसे ब्रिटेन से डिपोर्ट कर दिया गया था। उसे नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और फिर उससे पूछताछ की गई।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया शौर्य वाटिका का भूमिपूजन

शहीदों की स्मृति में सोनपुर में बनी शौर्य वाटिका, 37 शहीद परिवारों का हुआ सम्मान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। जिले के वीर बलिदानियों की पावन स्मृति को संजोने और उनकी शौर्यगाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम सोनपुर में शौर्य वाटिका का भूमिपूजन किया गया। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 37 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर लगभग एक एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही 'शौर्य वाटिका' में शहीदों के नाम पर उनके परिजनों द्वारा स्मृति वृक्ष लगाए गए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भी शहीदों की स्मृति में पीपल का पौधा रोपित कर शौर्य वाटिका में पौधरोपण की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लगभग 78.96 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें तालाब गहरीकरण, खेल मैदान, पहुंच मार्ग निर्माण, शौचालय, चबूतरा निर्माण, वृक्षारोपण एवं शेड निर्माण सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 37.95 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण, आहता निर्माण एवं शेड निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ के जवानों और बस्तर के लोगों ने बड़ी कीमते चुकाई है। उन्होंने शहीद जवानों और उनके परिवारों को नमन करते हुए कहा कि आज बस्तर में शांति स्थापित होने के बाद विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सल हिंसा के कारण स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थीं, वहां अब विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे में शहीद जवानों की बहादुरी और बलिदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज नक्सल क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जहां कभी जाना मुश्किल था, अब वहां शांति और बदलाव का माहौल है। उपमुख्यमंत्री ने सोनपुर गांव के विकास की सराहना करते हुए कहा कि यहां शहीदों की स्मृति में शौर्य वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के शहीद परिवारों और शहीदों के नाम पर यहां पौधरोपण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके त्याग और शौर्य को याद रख सकें। उन्होंने कहा कि सोनपुर गांव में योजना के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सरकार हरसंभव सहयोग करेगी। उपमुख्यमंत्री ने गांव में निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि मनरेगा सहित वीवीजी राम जी के माध्यम से रोजगार के साथ-साथ कौशल विकास और अधोसंरचना निर्माण को गति दी जा रही है।

प्राकृतिक आपदा से बचाव को लेकर बम्हनी में किया गया मॉँक ड्रिल

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन के संयुक्त तत्वावधान में बाढ़ से निपटने हेतु जिला स्तर पर बाढ़ मॉक एक्सरसाइज का आयोजन ग्राम बम्हनी में किया गया। कोंडागांव कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के नेतृत्व में बम्हनी के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी इंसिडेंट कमांडर, अपर कलेक्टर श्री चित्रकांत चाली ठाकुर, पर्यवेक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कपिल चंद्रा व सीआरपीएफ 188 बटालियन के डिप्टी कमांडर श्री मुकेश, नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री किशोर शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री लखेश्वर यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री राजेन्द्र कौशिक व तहसीलदार मनोज रावटे कोन्डागांव व नायब तहसीलदार श्री नरेंद्र सिंह एव समस्त अधिकारीगण के सहयोग मॉक एक्सरसाइज का आयोजन कर बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश व जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस विभाग, जिला सेनानी और स्वास्थ्य विभाग, जिला आपदा मोचन प्रबंधन बल, रेड क्रॉस सोसाइटी आदि शामिल थे। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ इत्यादि से निपटने हेतु आपातकालीन योजना बनाकर त्वरित राहत और बचाव कार्य एवं चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए एक मॉँक ड्रिल का आयोजन किया गया। ग्राम बम्हनी के जवाई मुंडा तालाब पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर जान बचाया गया एवं तत्काल उन्हें चिकित्सा सुविधा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनी ले जाया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सीपीआर की ट्रेनिंग भी दी गई। इस दौरान नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री नरपति पटेल, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री टोमेंद्र ठाकुर, ग्राम सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मॉक ड्रिल का अवलोकन किया।

पेपर लीक की सूचना मिलते ही कृषि मंत्री नेताम ने दिखाई सख्ती, तत्काल FIR और जांच के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना को कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने गंभीरता से लिया है। मामले की जानकारी मिलते ही मंत्री श्री नेताम ने विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल जांच समिति गठित करने तथा दोषियों के विरुद्ध स्नढ्ढक्र दर्ज कराने के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देशों के परिपालन में मामले में स्नढ्ढक्र दर्ज कर दी गई है। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता और विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रश्नपत्र लीक जैसी घटना अत्यंत गंभीर है और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध जांच के बाद कड़ी एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीएससी द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी विषय की आज आयोजित होने वाली परीक्षा के प्रश्नपत्र के लीक होने की सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले प्राप्त हुई थी। सुबह 8:50 बजे कवर्धा से प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10:30 बजे परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया। मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरस्त परीक्षा की आगामी तिथि जल्द निर्धारित की जाएगी और परीक्षार्थियों को इसकी सूचना समय पर दी जाएगी।

मॉकड्रिल: बाढ़ में डूब रहे लोगों को रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचाया

बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा, रामगढ़ में हुआ मॉक एक्सरसाइज

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाढ़ आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आज मुंगेली जिले में मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। मुंगेली जिले के ग्राम रामगढ़ स्थित अमृत सरोवर में आयोजित बाढ़ आपदा अभ्यास के दौरान जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों ने बाढ़ की स्थिति के दौरान राहत, बचाव एवं पुनर्व्यवस्था संबंधी कार्यों का अभ्यास किया। मॉक एक्सरसाइज में संभावित बाढ़ आपदा के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की उपलब्धता और राहत-बचाव कार्यों की प्रभावशीलता को परखा गया। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू कर आपदा के समय सतर्क रहने और सुरक्षित रहने के उपाय बताए गए। मॉकड्रिल में बाढ़ के दौरान बीच नदी में एक नाव पलटने का दृश्य प्रस्तुत किया गया। रेस्क्यू टीम ने तत्काल नाव से कुछ ही मिनटों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्हें सीपीआर देकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया तथा एंबुलेंस से बाढ़ राहत शिविर भेजा गया। मॉकड्रिल के दौरान पशुपालन विभाग ने भी पशुपालकों को बाढ़ के समय पशुओं को बीमारियों से बचाने के उपाय बताए। मुंगेली एसडीएम श्री अजय शतरंज ने बताया कि अभ्यास के दौरान नगर सेना एवं बचाव दल द्वारा आवश्यक उपकरणों एवं मोटर बोट के साथ बचाव कार्य की तैयारी का प्रदर्शन किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ के दौरान प्राप्त सूचनाओं के संकलन एवं नियंत्रण कक्ष में संचार व्यवस्था का अभ्यास किया गया। वन विभाग को प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई। प्लास्टिक की पानी की बोतलों, केले के थंभों और अन्य तैरने योग्य वस्तुओं की मदद से सुरक्षित स्थान तक पहुंचा जा सकता है। सर्पदंश की स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभ्यास स्थल पर चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, जीवन रक्षक दवाइयों एवं आवश्यक उपकरणों के साथ चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने का अभ्यास किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गो से अवरोध हटाने एवं आवागमन सुचारू बनाए रखने तथा पुलिस विभाग द्वारा वायरलेस संचार, यातायात एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्थाओं को परखा गया। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रभावित पशुओं के उपचार, विद्युत विभाग द्वारा विद्युत व्यवस्था, खाद्य विभाग द्वारा भोजन पैकेट, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल एवं जल निकासी तथा दूरसंचार विभाग द्वारा संचार व्यवस्था से संबंधित तैयारियों का अभ्यास किया गया। परिवहन विभाग द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मिनी बस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। राजस्व विभाग द्वारा राहत शिविर के संचालन, प्राप्त सूचनाओं के संकलन एवं वरिष्ठ अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाने तथा प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही का अभ्यास किया गया। पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा प्रभावित लोगों के ठहरने एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था को भी मॉक ड्रिल में शामिल किया गया।

क्षीरपानी जलाशय एवं भोंदा पुल पर जिला प्रशासन ने किया मॉकड्रिल

बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का किया गया अभ्यास, ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने का किया प्रदर्शन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कवर्धा जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज बोड़ला विकासखंड के क्षीरपानी जलाशय एवं ग्राम भोंदा पुल के समीप मॉकड्रिल आयोजित किया गया। मॉकड्रिल के दौरान अत्यधिक बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होने, जलाशय के ओवरफ्लो होने तथा ग्रामीणों के गहरे पानी में फंसने की काल्पनिक स्थिति तैयार कर मॉकड्रील किया गया। इस दौरान राज्य से टीम भी वीड़ियों कांन्फ्रेस के माध्यम से जुड़ी रही। मॉकड्रिल के तहत मैकल पर्वतीय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण क्षीरपानी जलाशय के अधिकतम जलभराव क्षमता तक पहुंचने और ओवरफ्लो की स्थिति निर्मित होने की सूचना दी गई। इस दौरान चार ग्रामीणों के जलाशय के गहरे पानी में फंसने तथा तारेगांव जंगल मार्ग पर ग्राम भोंदा के समीप पुल बाढ़ के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति का अभ्यास किया गया। पुल क्षतिग्रस्त होने से आसपास के कई गांवों का संपर्क बाधित होने की काल्पनिक स्थिति निर्मित की गई। स्थिति की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों द्वारा जिला बाढ़ कंट्रोल कक्ष को सूचना देने और तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू करने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। अपर कलेक्टर श्री रामप्रसाद आँचला ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए जिला बाढ़ आपदा एवं प्रबंधन टीम में शामिल नगर सेना एवं एनडीआरएफ की संयुक्त टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया। सुबह 10 बजे संयुक्त दल क्षीरपानी जलाशय पहुंचा और राहत एवं बचाव अभियान प्रारंभ किया। मॉकड्रिल के दौरान नगर सेना, एनडीआरएफ के विशेषज्ञ जवानों, जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों की रैपिड एक्शन टीमों ने आपसी समन्वय के साथ राहत-बचाव कार्यों का अभ्यास किया। जलाशय में फंसे चार ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने तथा ग्राम भोंदा में क्षतिग्रस्त पुल के दूसरी ओर अलग-थलग हुए ग्रामीणों तक वैकल्पिक पुल बनाकर बाहर निकालने, आवश्यक सहायता पहुंचाने की कार्रवाई का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आपदा की स्थिति में सूचना प्राप्त होने से लेकर राहत एवं बचाव दल की तैनाती, प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। मॉकड्रिल के दौरान बोड़ला एडीएम श्री आशुतोष शर्मा, तहसीलदार श्री हुलेश्वर पटेल सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। विभिन्न विभागों द्वारा आपदा के दौरान अपने-अपने दायित्वों के अनुरूप की जाने वाली कार्रवाई का भी अभ्यास किया गया।

नक्सली हिंसा से प्रभावित 8 पीड़ितों को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के तहत जिला प्रशासन द्वारा पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री विश्वदीप ने नक्सली हिंसा से प्रभावित 8 पीड़ितों के लिए कुल 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। प्रत्येक लाभार्थी को 5-5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने भी नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रभावित नागरिकों और परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन की ओर आगे बढ़ने में सहयोग देना है। मृतकों के परिजनों और स्थायी रूप से असमर्थ व्यक्ति को मिलेगी सहायता स्वीकृत सहायता नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के निकटतम वारिसों तथा स्थायी रूप से असमर्थ व्यक्ति को दी जाएगी। लाभान्वित होने वालों में सोयम धरमा की पत्नी श्रीमती सोयम सीता, धरमैया ध्रुवा की पत्नी श्रीमती मुन्नका ध्रुवा, बाड़से पिंटू की पत्नी श्रीमती हड़मे बाड़से, कवासी जोगा की पत्नी श्रीमती मंगली कवासी, चन्द्रैया मोड़ियम के पिता श्री मारा मोड़ियम, तुलेश्वर राणा के पिता श्री कमलसाय राणा, कुरसम मंगलू के पुत्र श्री नंदू कुरसम तथा स्थायी रूप से असमर्थ श्री राजू मोड़ियम शामिल हैं। शेष 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में तीन वर्ष की सावधि जमा (एफडी) के रूप में रखी जाएगी।

हरियाणा प्रांत की शराब तस्करी एवं कच्ची महुआ शराब के विक्रय पर आबकारी विभाग की कार्रवाई

● कच्ची महुआ शराब एवं 200 किलो महुआ लाहन बरामद ●

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कवर्धा जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने 17 अगस्त 2026 को अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अन्य प्रांत हरियाणा की मदिरा का अवैध परिवहन करने तथा कच्ची महुआ शराब का विक्रय करने वाले कुल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में मदिरा, महुआ लाहन एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन सहित कुल 8 लाख 16 हजार 310 रुपये की सामग्री जब्त की गई है। आबकारी आयुक्त श्री पदुम सिंह एल्मा एवं कलेक्टर के निर्देश तथा प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश पाण्डेय के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश पाण्डेय ने बताया कि 17 अगस्त 2026 को आबकारी चेक पोस्ट चिल्फी के प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री रामानंद दीवान द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान चार पहिया वाहन क्रमांक एचआर 36 एबी 0487 की विधिवत तलाशी लेने पर वाहन से 5.25 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, जिस पर सेल फॉर हरियाणा अंकित था, बरामद की गई। मदिरा को विधिवत जब्त करते हुए आरोपी विक्रम सिंह पिता आजाद सिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम अमलीडीह, पोस्ट बरगड़ा, जिला बेमेतरा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) एवं 36 के तहत गैर-जमानती प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक श्री विद्यासिंह परमार, श्री इम्तियाज खान तथा आबकारी आरक्षक श्री भूपेंद्र साहू, सुश्री कामिनी भुआर्य, मेघा ध्रुव एवं सीमा नेताम का विशेष योगदान रहा।

बिहान समूह की महिलाओं ने हुनर को बनाया आमदनी का जरिया राखी निर्माण और बकरी पालन से बढ़ रही आय, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया कदम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़कर जिले के ग्राम फुलवारी की सरस्वती स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। महिलाएं एक ओर बकरी पालन को आय का स्थायी साधन बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय संसाधनों और अपने हुनर का उपयोग कर पर्व-त्योहारों के अवसर पर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रही हैं। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर सरस्वती स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आकर्षक राखियां तैयार कर अपने हुनर को बाजार तक पहुंचाया। महिलाओं द्वारा स्थानीय एवं प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की सुंदर राखियां तैयार की गई। समूह की महिलाओं ने कलेक्टोरेट के सामने राखी विक्रय के लिए स्टॉल लगाया, जहां जनदर्शन में पहुंचे आमजनों ने महिलाओं द्वारा तैयार राखियों की खरीदारी की और उनके हुनर की सराहना की। राखियों की बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हुई, वहीं अपने हाथों से तैयार उत्पाद को लोगों द्वारा पसंद किए जाने से उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। महिलाओं ने बताया कि इस तरह के अवसर उन्हें घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। समूह की सदस्य श्रीमती सुनीता और श्रीमती अंजू धुरी ने बताया कि बिहान समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला है। समूह की महिलाओं को बकरी पालन के लिए सहायता स्वीकृत हुई है, जिसके माध्यम से वे अपनी आजीविका को मजबूत करने और नियमित आय का साधन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। बकरी पालन जैसी गतिविधियों से महिलाओं को गांव में ही रोजगार का अवसर मिल रहा है और वे परिवार की आर्थिक जरूरतों में सहयोग कर पा रही हैं। बिहान समूह के माध्यम से महिलाओं को केवल आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का अवसर ही नहीं मिल रहा, बल्कि उनके हुनर को पहचान और बाजार भी मिल रहा है। राखी निर्माण जैसी मौसमी गतिविधियों से महिलाएं स्थानीय मांग को अवसर में बदलकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। वहीं बकरी पालन के माध्यम से दीर्घकालिक आजीविका का आधार तैयार कर रही हैं।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा